Press Council. Therefore, we have to go to the third limb which is very proper in the circumstances, because after all, the fourth estate is called the fourth limb of the state.

Shri K. C. Sharma: What has led the hon. Minister to bring the Chief Justice into this? Could he not find any other organ?

Shri C. R. Pattabhi Raman: The Indian Federation of Working Journalists wanted it. It was also in the original Bill.

Mr. Chairman: It is too late to raise this question after the discussion is over.

The Question is:

"That this House concurs in the recommendation of Rajya Sabha that the House do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to establish a Press Council for the purpose of preserving the liberty of the Press and of maintaining and improving the standards of newspapers in India, made in the motion adopted by Rajya Sabha at its sitting held on the 15th September 1964, and communicated to this House on the 17th September, 1964, and resolves that the following 30 Members of Lok Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely: Shri Peter Alvares; Shri C. K. Bhattacharyya; Shri N. C. Chatterjee; Shri Tridib Kumar Chaudhuri; Shri Yudhvir Singh Chaudhary; Shri C Dass; Shri L. Elayaperumal; Shri Ansar Harvani; Shri T. D. Kamble; Shri Cherian J. Kappen; Sardar Kapur Singh; Shri M. K. Kumaran; Shri Nihar Ranjan Laskar; Shri Shiv Charan Mathur; Shri Mathura Prasad Mishra; Shrimati Sharda Mukerjee; Shri Mohan Nayak; Shri Man Sinh P. Patel; Shri Kishen Pattnayak; Shri Shivram Rango Rane; Shri Sadhu Ram; Shri Sham Lal Saraf; Pandit K. C. Sharma; Shri Shashi Ranjan; Shri Vidya Charan Shukla; Dr. L. M. Singhvi; Shri Tula Ram; Shri S. Veerabasappa; Shri Virbhadra Singh, and Shri C. R. Pattabhi Raman.".

The motion was adopted.

15.28 hrs.

DISCUSSION *RE*: FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

Mr. Chairman: We are nearing 3.30 p.m. I think it is agreed that we should discuss this for 2½ hours, that is till 6 p.m.

Shri Warior (Trichur): In the order paper it was put that the Industrial Disputes (Amendment) Bill would be taken up. Let us know when it would be taken up.

Mr. Chairman: I was present when the Deputy Speaker decided about the course of business here. It was agreed that this discussion would go on till 6 p.m. Afterwards, no other business will be taken up for the day. Therefore, the hon. Member's question does not arise now. It may come tomorrow.

Regarding this discussion, there are a large number of Members wishing to speak. There should be some self-imposed timelimit. One view is in favour of 10 minutes per speaker. Members speaking later will not require so much time. Shri Bagri is the mover. I can allow him 15 minutes. He should strictly adhere to this time-limit. The flood situation is a problem that affects the whole country, and representatives from every State are anxious to ventilate their difficulties. The situation has not arisen so recently yesterday or today, and it is a continuing one in all the States. Therefore, I should like to distribute the time in such a way that every State gets its quota of time.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): More floods, more time.

Mr. Chairman: No. That way, we will be choked. More floods, less time.

Shri Bade (Khargone): There are six signatories to the motion. They should be given time.

Mr. Chairman: There are signatories all right, but there are others from all sides of the House who want to speak. I will see how it can be adjusted.

श्री बागड़ी : सभापति महोदय, एक बात मैं अर्ज करूंगा कि इस से पहले भी इस तरह की चर्चायें उठती रही हैं। लेकिन इस तरह से कभी पन्द्रह मिनट की पाबन्दी पहले आदमी पर नहीं रही है बोलने की। मैं पहली दफ़े अपने लिये ऐसा सुन रहा हूं। जो पन्द्रह मिनट की पाबन्दी बान्ध रहे हैं मेरे लिये ऐसी कोई व्यवस्था पहले नहीं हुई इस सदन में। यह पहली बार हो रहा है।

Mr. Chairman: I have said that he will get 15 minutes. Let him proceed with his speech.

श्री बागड़ी : पन्द्रह मिनट में तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, 5 सितम्बर, 1962 को इसी सदन में मैंने इसी बाढ़ के ऊपर चर्चा को उठाया था। उस वक्त मन्त्री महोदय कोई और थे। बाढ़ की चर्चा यहां से उठी। आज वह मन्त्री नहीं। यह बात दूसरी है कि आज मन्त्री और सज्जन बैठे हैं। शायद बाढ़ का तूफान उन मन्त्री महोदय को वहां ले गया क्योंकि वह किसी तरीके से उसको काबू में नहीं कर सके।

इस बाढ़ की चर्चा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दो प्रदेशों को छोड़ कर अट्ठारह प्रदेशों में इस वक्त भयंकर बाढ़ है। बाढ़ जब आती है तो एक किस्म का प्रदर्शन होता है, सरकार की तरफ से भी और बाहर से नेताओं और जनता की तरफ से भी। बाढ़ आई। हवा के अन्दर हवाई जहाजों में मन्त्री और बड़े लोग भी घूमते हैं, कारों और मौकाओं में मध्यम श्रेणी के लोग घूमते हैं और दूसरे लोग भी तरह तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मुस्तकिल तौर पर यह बात नहीं जमा पाते कि किस तरीके से इस देश में इस बाढ़ का अन्त किया जाये। इससे पहले कि मैं बाढ़ के बारे में यह बात रखूं कि क्या और क्यों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं कि बाढ़ सिर्फ खुदाई कहर नहीं है, यह सिर्फ खुदाई देन नहीं है। सन् 1945 से पहले हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहा करते थे कि बाढ़ सिर्फ खुदाई देन नहीं, बल्कि वह अंग्रेज शासकों के भ्रष्टाचार और उनके अन्याय की देन है। उसके बाद मैं देश के महान् पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों को दोहरा देता हूं जो कहते थे कि जो सरकार बाढ़, रोग और भुखमरी जैसे पापों से मुक्त होने के लिये यह कह कर अपना पिंड छुड़ाना चाहती है कि यह दोष हमारा नहीं, भगवान् की देन है, यह प्रारब्ध की बात है, वह सरकार कभी पाप से मुक्त नहीं होती। जनता जागृत होती है और उस सरकार को पापों का दण्ड देती है।

मैं अर्ज करूंगा कि आज हिन्दुस्तान की एक करोड़ जनता इस बाढ़ के अन्दर ग्रस्त है। बाढ़ तीन तरीके से आती है। एक तो नदियों में पानी का बहाव ज्यादा हो जाने से दूसरे बारिश ज्यादा हो जाने से और तीसरे पानी के काफी दिन तक खड़े रहने से नीचे से सेम के रूप में पानी के आ जाने से। जो बाढ़ हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेजों की देन थी वह देन आज भी बदस्तूर है। यानी वह रेल, वह सड़क, वह नहरें जो अंग्रेजों ने अपने मफाद के लिये निकाली थीं, उनको यहां यह देख कर नहीं निकाला था कि इस तरीके से लेवल रखने से जनता दुखी होगी। इससे उसे कोई मतलब नहीं था कि उसका काम कैसे चलेगा, उसको सुविधा और आराम कैसे होगा। उसमें से जो पाप निकला बाढ़ का वह बदस्तूर कायम है ही, लेकिन आज की सरकार भी इस बात की दोषी है कि इसके कर्मों से

भी बाढ़ बढ़ा है । जिस तरह से सड़कें, नहरें और रेलें हैं उसी तरह से इस सरकार ने भी बांध बांधे । जब उसने ऐसा किया तो वह इसके तीन परिणाम देश के सामने रखती थी कि बांधों से क्या होगा । एक तो यह होगा कि बांध से पानी मिलेगा, दूसरे बिजली मिलेगी और तीसरे बाढ़ रुकेगी । मैं सदन में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि बड़े बांध बिल्कुल अपने परिणाम को नहीं पा सके हैं, बल्कि फेल हुए हैं । अगर थोड़ी बहुत पानी और बिजली की बात मान भी ली जाये, तो भी बाढ़ के लिये हिन्दुस्तान के बांध लाभदायक नहीं बल्कि हानिकर साबित हो रहे हैं । उन्होंने खुद हिन्दुस्तान के अन्दर बाढ़ पैदा की है । इसलिये कि यह नहरें, यह रेलें और यह सड़कें, असल में ठीक लेवेल पर नहीं हैं । उनके नीचे छोटे छोटे पुल और साइफन नहीं हैं, जिन से पानी निकल सके । हर चीज जो दुनिया के अन्दर आती है उसके जाने का रास्ता भी कुदरत साथ देती है । इसी तरह से पानी का कुदरती बहाव होता है । तीन किस्म के दुःख पानी ने इस देश में पैदा कर रखे हैं । एक तो नदियों में बाढ़ आई असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में । राजस्थान का मैं जिक्र नहीं करूंगा, रोहतक, करनाल . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा): जरूर कीजिये राजस्थान का जिक्र ।

श्री बागड़ी : मैं राजस्थान का जिक्र नहीं कर रहा हूं । आप जरा सुनिये । मैं जिक्र नहीं करूंगा हिसार का, रोहतक का, करनाल का, क्योंकि स्वामी रामेश्वरानन्द, श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती, श्री लहरी सिंह आदि खुद इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, वे स्वयम् इस पर बोलेंगे ।

एक तो बाढ़ आई नदियों से, दूसरे बाढ़ आई बरसात से और तीसरे बाढ़ आई सेम से । तीनों किस्मों की बाढ़ें इस देश की जनता को ग्रस्त करती जाती हैं । सन् 1962 के बाद दो साल के अर्से में हमारी कांग्रेस सरकार सो गई । जब बाढ़ आई तो जलूस निकले, बाढ़ चली गई है जलूस खत्म हो गये । फिर चिन्ता नहीं । जब बाढ़ आती है और लोग शोर मचाते हैं तो हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि किश्तियां थोड़ी हैं । क्यों साहब, आपको किश्तियों की तब याद आती है जब बाढ़ आती है । हमारी सरकार तो ऐसी है जो कहती है है कि जब प्यास लगती है तो कुआं खोदो । बाढ़ से पानी आ गया । बाढ़ इस देश के अन्दर आती है, मानता हूं । लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी की बात अगर किसी जनतान्त्रिक देश के अन्दर कोई सरकार करती होती और उस जनता में शक्ति होती, जो दुःख आज बाढ़ से हिन्दुस्तान की गरीब जनता को है, अगर वह इस देश के पढ़े लिखे और दर्म्याने तबके के लोगों का होता, तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक क्रान्ति हो जाती, बगावत हो जाती, और जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं शायद जनता उनको तख्तबरदार कर देती या जला देती । आज हिन्दुस्तान की जनता का इतना नुकसान हुआ तब यह कितनी गैर जिम्मेदारी की बात है कि साहब, किश्तियां नहीं हैं । क्यों साहब, क्या किश्तियां बनाने में बड़ा जोर लगता है । अगर आप बना सकते हैं चण्डीगढ़ और उस पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं, दिल्ली में बड़े बड़े महल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बना सकते हैं, तब जब आप को पता है कि बाढ़ आयेगी तब आप उसके लिये कुछ नौकायें नहीं बना सकते । मैं अर्ज करूंगा कि उनके लिये नौकायें नहीं, वक्त पर उनको रोटी नहीं । कल कांग्रेसी भाइयों ने एक प्रदर्शन किया, नजफगढ़ के लोगों ने । उनमें औरतें थीं, बच्चियां थीं, बच्चे थे, भूखे थे, दरिद्र लोग थे । एक महीने से उनके खेतों में पानी पड़ा है । आज पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में, पानी ने एक भयंकर भुचाल सा ला दिया है, जहां जहरीले जानवर सांप,

[श्री बागड़ी]

बिच्छू पानी के ऊपर तैरते हैं और गरीब किसानों और दलित लोगों की जिन्दगियां पानी में खड़ी हुई हिन्दुस्तान का इस तरह का दृश्य दिखला रही हैं कि मांयें अपने बच्चों को छाती से चिपटाये खड़ी हैं क्योंकि उनके बैठने के लिये जगह नहीं, सोने को जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, छाती से दूध नहीं आता है, उसका पाप उसका खन चूसता है, लेकिन यह सरकार उसे मदद नहीं दे सकी। यह हिन्दुस्तान की सरकार का एक भयानक दौर है, कब तक इसको जनता देखेगी और बर्दाश्त करेगी।

मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत सरकारी आंकड़े होते हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ पंजाब के अन्दर, लेकिन रकबे का पता नहीं। रकबे का पता इसलिये नहीं कि इन्फार्मेशन नहीं आई प्रदेशों से। इतनी भयंकर बाढ़ें आ गई हैं, लेकिन रकबे की इत्तला नहीं आई। अब बोलिये साहब, कब आयेगी इत्तला। एक बड़े ताज्जुब की बात यह कि पंजाब ने तीन पम्पिंग सेट मंगवाये थे। पंजाब से वादा भी किया गया था लेकिन वह भेजे नहीं गये। क्यों। क्या वह भी रूस और अमरीका की बात थी कि वादा करके नहीं भेजा। एक प्रान्त सरकार की सरकार दूसरे प्रान्त के वास्ते चीज न भेजे।

और एक सबसे बड़ी बात पाप के गर्भ में से निकल रही है। एक तरफ तो पंजाब डूब रहा है, दिल्ली डूब रही है, राजस्थान डूब रहा है, उत्तर प्रदेश डूब रहा है और दूसरी तरफ शासक अन्याय के गर्भ से यह पाप निकाल रहे हैं कि पंजाब से कहते हैं कि तुम को यू० पी० डुबा रहा है, राजस्थान से कहते हैं कि तुमको पंजाब डुबा रहा है और इस प्रकार एक प्रान्त को दूसरे से लड़ा रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पानी को निकाला जाए और लोगों को आबाद किया जाए, लोगों को लड़ाने की जरूरत नहीं है। कल जो प्रदर्शन हुआ उसमें झण्डा तो कांग्रेस का था और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे और कहा जा रहा था कि तुमको किसने डुबोया, पंजाब ने। मैं तो कहता हूं कि न पंजाब डूबना चाहिए, न दिल्ली डूबनी चाहिए, न उत्तर प्रदेश डूबना चाहिए, न मध्य प्रदेश डूबना चाहिए, हिन्दुस्तान का कोई किसान या गरीब नहीं डूबना चाहिए। मैं डूबने के कतई हक में नहीं हूं। लेकिन अगर किसी को डुबोना है तो चरत राम और भरत राम के मिल को क्यों नहीं डुबोते जिसको बचाने के लिए नजफगढ़ नाल को खराब कर दिया और जिसके कारण दिल्ली की जनता को खराब पानी पीना पड़ रहा है। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता क्योंकि या तो वे दिल्ली के चीफ कमिश्नर के रिश्तेदार हैं या पूंजीपति हैं। आज एक महीने से पानी भरा है जिसे नहीं निकाला जा रहा है।

सरकार ने बाढ़ की परिस्थिति में लोगों की मदद की है, लेकिन कितनी मदद दी है। असल में तो मदद का कोई ढंग ही नहीं है। कहते हैं कि पंजाब में 60 आदमी मरे और कुल 148 आदमी मरे हैं। हम देखते हैं कि जब तरक्की की बात आती है तो कर्मचारी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और जब जनता के नुकसान की बात आती है या जनता के दुख दर्द की बात आती है तो तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कोई दुःख है ही नहीं, अगर कहीं दुःख है तो मन्त्रियों के दिल में है बाहर कहीं नहीं है। तो यह तरीका गलत है। यह देश के मन को गिराएगा, यह देश की मर्यादा को भंग करेगा।

मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन बातों की तरफ ध्यान देकर इस सदन को कुछ फैसला करना चाहिए। इस चर्चा के गर्भ से कुछ निकालना चाहिए। इसके दो रास्ते हैं, एक तो स्थायी इलाज और

दूसरा फौरी इलाज । जहां तक स्थायी इलाज का सवाल है कल मुझे लोहिया साहब ने बताया था कि जो 25 हजार मील में रेल की पटरी है अगर इसको ठीक लेविल में कर दिया जाए तो बाढ़ का काफी हिस्सा मिट सकता है । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सरकार प्रतिष्ठावाद को छोड़े । कोई काम करते हैं तो तो प्रतिष्ठा का सवाल पहले सामने रखते हैं । तो सरकार को इसे छोड़ना चाहिए और जो निर्णय ले उस पर अमल करना चाहिए । सिद्धान्त और आदर्श को आगे रखना चाहिए ।

यहां विज्ञान की बात कही जाती है । विज्ञान के बारे में मैं एक बात कहूं । मुझे यह कहते लज्जा आती है कि वे कोई और देश होंगे जिनमें वैज्ञानिक पहाड़ों पर दरिया को चढ़ा देते हैं, यहां तो यह बात नहीं हो सकती । हिन्दुस्तान में तो यह बात होने वाली नहीं है । यहां कहा जाता है कि विज्ञान के कारण उद्योग में तरक्की हुई है । लेकिन क्या तरक्की की है । मैं तो कहता हूं कि विज्ञान के द्वारा जनता के मन को बढ़ाओ । कुछ निर्णय लो और उनको पूरा करो । यह फैसला करो कि हम हिन्दुस्तान की इतनी जमीन को छोटे तरीकों से पानी देंगे । यह फैसला करो कि इतनी सेम जदा जमीन में से पानी निकालेंगे । यह फैसला कीजिए कि इतने छोटे छोटे बांध बनायेंगे या इतनी पुलियाएं बनायेंगे जिनसे बाढ़ का पानी निकल सके । केवल उद्योग की बात कह दी जाती है कि उसमें तरक्की हुई है । मैं पूछता हूं कि उद्योग में अंग्रेजी राज्य में हिन्दुस्तान का दुनिया में आठवां नम्बर था, आज कोई बताए कि कौनसा नम्बर है । यह तरक्की है उद्योग की ।

हर बात को गलत ढग से पेश किया जाता है । मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक फौरी इमदाद का सवाल है यह फैसला किया जाए कि सेम जदा इलाके से सेम निकाला जाए और नदियों से जो बाढ़ आती है पानी के ढलान के कारण उसका बुनियादी तौर पर इन्तिजाम किया जाए जिससे न रोहतक डूबे, न दिल्ली डूबे, न राजस्थान डूबे, अगर कोई डूबे तो वे लोग डूबें जिनके पाप कर्म लोगों को डुबा रहे हैं ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नदियां जो आती हैं तो अपने साथ रेता लाती हैं और कटाव करती हैं । इस तरह वे चौड़ी ज्यादा होती जाती हैं और गहरी कम होती जाती हैं । इसके लिए जरूरी है कि नदियों की खुदाई करायी जाए और उनके किनारों को मजबूत किया जाए ।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि फौरी मदद के नाम पर पंजाब को 68 लाख रुपया दिया गया और इतने ही आदमी वहां बाढ़ से पीड़ित हैं, यानी एक आदमी को एक रुपए की मदद दी गयी और हातिम ताई जैसी बातें करते हैं । फौरी मदद के सिलसिले में मैं चार पांच बातों का सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं । जो फसलें तबाह हो गयी हैं उनका तमाम मुआवजा दिया जाए, सरकार का जितना आबियाना, माल आदि का बकाया है उसको माफ किया जाए, फौरी तौर पर उनको राशन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए क्योंकि सरदी का मौसम आ रहा है । बच्चों की मुफ्त तालीम का प्रबन्ध किया जाए और और लोगों के लिए दवा का इन्तिजाम किया जाए, पशुओं के लिए चारे का इन्तिजाम किया जाए, और चूंकि इन इलाकों में अन्न नष्ट हो गया है और बुवाई का समय है इसलिए इस इलाके में लोगों को मुफ्त बीज दिया जाय ताकि वे खेती कर सकें, और नजफगढ़ वगैरह इलाकों से पानी को निकाला जाए । तो मैं कहना चाहूंगा कि सदन गम्भीरतापूर्वक सोच कर कुछ निर्णय ले और उस पर पूरा अमल करे । राज्य सरकारों से अभी पूरी सूचना नहीं आयी है । मुझे राम किशन सरकार का पता है कि उन लोगों ने अभी तक इनफारमेशन नहीं दी है ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : राज्यों से फिगर आने पर निर्णय किया जा सकता है ।

श्री बागड़ी : अभी राज्यों से इनफारमेशन एवेट की जा रही है। क्या ये आंकड़े तब आएंगे जब बाढ़ चली जाएगी या जब जनता की बाढ़ के कारण मन्त्रिमण्डल चला जाएगा। कब आएंगे ये आंकड़े ? पंजाब में यही हाल है, मध्य प्रदेश का यही हाल है और तकरीबन जितने आंकड़े हैं उनके बारे में मैं पंजाब के आंकड़ों को देखते हुए कह सकता हूं दावे के साथ कि वे बिल्कुल गलत हैं। मैं कहूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को महसूस करे। एक बेचारे के० एल० राव हैं जो भागते फिरते हैं। लेकिन वह एक अपंग आदमी हैं। वह तो एक राज्य की इत्तिला दूसरे राज्य को देते हैं, इससे ज्यादा उन्हें ताकत नहीं। ताकत है सारे मन्त्रिमण्डल को। सारा मन्त्रिमण्डल इसको सोच कर फैसला करे और जो इस वक्त दुःख और संकट है उसको फौरी तौर पर दूर करने का मुकम्मल इन्तिजाम करे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बहस के गर्भ में से कुछ नतीजे निकाले। एक गांव को बचाने के लिए एक इलाके को न डुबाया जाए, एक मिल को बचाने के लिए दिल्ली को न डुबाया जाए।

आज कहा जाता है कि दिल्ली के अन्दर सवा लाख आदम बाढ़ से पीड़ित हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 25 लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हैं। क्या जो लोग गन्दा पानी पी रहे हैं वे सब बाढ़ से पीड़ित नहीं हैं। तो मैं अन्त में कहूंगा कि इस तरह के गलत आंकड़ों का तरीका भी बदलो।

Some hon. Members *rose—*

Mr. Chairman: Shri D. C. Sharma.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : सभापति महोदय, जिस क्रम में यह नाम दिये गये हैं उस तरह से न बुला कर क्या बीच वालों को छोड़ देंगे ? कृपया क्रम से चलिए।

Mr. Chairman: I am apportioning the time. I will try to see that every section of the House gets its time. I must have the freedom to arrange the debate.

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जिन लोगों ने नोटिस दिया है उनको सभापति महोदय को पहले लेना चाहिए और उसी क्रम से उन्हें बुलाना चाहिए।

सभापति महोदय : स्वामी जी, आप बैठ जाइये।

श्री इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : सभापति जी आपको बैठने के लिए कह रहे हैं इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : सरदार जी को शायद पता नहीं है कि किस तरीके से बहुत कुछ लिखा पढ़ी और कहने सुनने के बाद यह मोशन आज हाउस के सामने आ सका है। फिर मैंने तो सभापति महोदय से यही चाहा है कि वे क्रम से लें...

सभापति महोदय : क्रम का भी निर्णय करने वाला मैं ही हूं। स्वामी जी, अब बैठ जायें। सभी लोगों को मौका मिलेगा (इंटरप्शन्स)।

Mr. Chairman: Punjab is not inhabited only by representatives from the Opposition or the Congress Party. All parties are represented here. Therefore, every party will get its time according to its strength.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, at the very outset I wish to submit that the calamity which has overtaken almost all the States in India is not the first of its kind. I want to ask the Government of India, when this calamity occurs every year, when we are told about this Najafgarh area, when we are told about Jumna, Bagmati and other rivers where flood takes place, why is it that the Government does not take due precautions to stop these floods? Sir, prevention is the better part of cure. I know that when floods occur the Government does everything in its power to

help the people. But in spite of that, cattle are destroyed, lands go under water, human lives are lost and so many other calamities overtake our population.

I would like to ask the hon. Minister one question. India has been free for the last 17 years and these floods have been occurring every year. Why is it that they have become hardy annuals, why is it that they have become annual occurrences, and why is it we are asked to debate this point every time in this House. Therefore, I think it is the duty of the Government and the duty of every Member of this House to whatever party he may belong, to take not only long-term measures for the prevention of these floods but also short-term measures so that the population is not put to any trouble every year.

I do not want to go into the extent of damage that has been brought about by these floods. I think the hon. Minister has been very candid in this matter. If I may be permitted to say so, it is for the first time that we have got a very reliable report from the Government. Of course, there are some persons who may differ from this report. They may say that the damage is greater than what is given in the report of the Government.

An Hon. Member: Because they are not dependable.

Shri D. C. Sharma: But there is no doubt about the fact that the Government has been very fair with us, very fair with the population, very fair with the people of the country and very fair with those people who are affected. How are these losses to be made good—the loss of crops? Of course, nobody can make good the loss suffered on account of loss of human lives. Who can do anything about that? My heart goes out to all those persons who lost their lives during these floods, and I think the whole House is full of sympathy for those persons. . . .

Dr. M. S. Aney: For their relatives.

Shri D. C. Sharma: I want to ask the Government whether they are going to do something for the survivors of those persons. It is the moral duty of the Government to do something for the families of those persons who lost their lives in the floods.

My second point is this. Only this morning some persons came and told me that so many houses have fallen down. A gentleman came and told the story of Sonepat. The same story is repeated everywhere. The same story is more or less to be found in my constituency also. The same story is to be found in all parts of India—Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal and other States. Here is my hon. friend from Midnapur. He has suffered from floods. I would say, the Government should do something to make good the losses that the farmers have suffered on account of their crops being damaged altogether by these floods. Why do I say so? Unless the Government pay the penalty for its neglect, the penalty in terms of money, the penalty in terms of *prayaschith*, I think these floods will not become things of the past, these floods will go on occuring every year.

My third point is this. The hon. Minister has given us two statements. I have gone through both these statements. We know where the disease is, what the trouble spots are, which of the rivers are dangerous and how the whole thing starts. I would say that the Government should prepare, first of all, a short-term plan for those cities and villages which are affected every time these floods occur. I would also say that the Government should have blue-prints of those rivers which are causing us trouble. It will be said that it is very difficult to control these rivers, that Kosi is known as the river of sorrow, that Bagmati is an erratic river, that Beas is a river which is as whimsical as you can imagine it to be and so on. But all these things

[Shri D. C. Sharma]

do not cut any ice with this House today. I would, therefore, say that a high-power commission should be set up to prepare village-wise account, to prepare a blueprint for the protection of every village that is affected, every city that is affected by these rivers which are causing us trouble.

15.59 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

I want to ask one other thing. What is the reason that whenever we are in trouble we send for the army? What is the reason that whenever we are in trouble we send for the navy? Why is it that our civilian population cannot cope with these disasters?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : आप का काल समाप्त हो गया है ।

श्री दी० चं० शर्मा : काल आपका समाप्त होने वाला है । मैं तो अभी बहुत दिन जिन्दा रहने वाला हूं ।

So, I was submitting very respectfully that something has got to be done. I know that the hon. Minister will say something to alleviate the human suffering, to bring hope to the minds of the affected persons. I say that will not be enough. We want to have a foolproof remedy for these ills which are recurring every day, every year; unless that is done, the trouble will go on recurring. It may be said that we will require so many crores of rupees, that the whole Five Year Plan money will have to be spent on it. I may tell you that the population of India is not prepared to listen to these things because, as it has been stated, these calamities are due to three causes. The rainfall is there. But what about drain No. 8 and drain No. 6? There is no effective construction of drains. Those drains were not deep enough and strong enough and so breaches occurred. Therefore, it is not God-made malady but man-made malady. It has been created by man. Therefore, you should take action against the persons who have constructed this defective drain. You have to entrust the whole case to some establishment like the SPE to see why this drain was constructed in such a defective manner that it could not stand the floods.

16.00 hrs.

Therefore, I would say that while we have got to look to the needs of the people who are in distress and have to satisfy those needs as fully as possible, while we have to see that such floods do not take place in future, we have also to see that those drains and bunds which were man-made and that too under the supervision of engineers are in good condition. Therefore, Government has to order an all-round, all-out, foolproof, unbiased enquiry into these happenings. It should place before this House not only a long-range plan but also a short-term plan. Dr. K. L. Rao is a person who knows all these things. I hope he will be able to satisfy us in such a way that next time no debate on floods takes place in this House and even if there are floods there are no damages to human life, crops and other things and everything goes on smoothly.

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली करौलबाग) : सभापति जी, आज हम यहां पर बाढ़ की समस्या पर विचार कर रहे हैं । देश में हर साल बारिश आती है, बरसात होती है, नाले उबलते हैं, नदियां अपने तट-बन्धों को छोड़ देती हैं, सब जगह पानी फैल जाता है और फिर वही परेशानियां हमारे सामने आती हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हम सारे देश के लिये एक ऐसा नक्शा तैयार करें, जिसमें किसी भी सीमा की कोई रोक नहीं होनी चाहिए, किसी प्रदेश की कोई रोक नहीं होनी चाहिए ।

अक्सर यह देखा गया है कि एक प्रान्त वाले अपने पानी को निकाल कर दूसरी जगह लाकर छोड़ देते हैं और दूसरे प्रान्त वाले उससे परेशान रहते हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या वह अपने घर से पानी लाकर छोड़ देते हैं ?

एक माननीय सदस्य : चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं वह भी बता दूंगा ।

इस अवस्था में हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह पानी रुकने न पाए और हर बरसात में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े ।

मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन श्री सिद्धान्ती ने मुझे कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि बरसात दिल्ली में नहीं हुई, पंजाब में हुई और परेशानी दिल्ली वालों को भुगतनी पड़ी । पंजाब वालों ने नाला नम्बर 8 खोदा और ड्रेन चेम्बर 6 खोदी और उनका लाकर दिल्ली के पास छोड़ दिया कि दिल्ली डूबती रहे । पंजाब वालों ने जो नालियां खोदीं, उन में उन्होंने पंजाब की तरफ तो मिट्टी डाल दी और दिल्ली की साइड पर मिट्टी नहीं डाली, ताकि नालों में पानी बढ़ेगा तो वह दिल्ली की तरफ चला जायेगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : "दिल्ली चलो" ।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : रांग स्टटमेंट ।

श्री नवल प्रभाकर : यह रांग स्टटमेंट नहीं है । मैं माननीय सदस्य को साथ ले जा कर दिखला सकता हूं ।

Shri D. C. Sharma: I think this debate should be kept free from provincial rivalries and acrimonies.

श्री नवल प्रभाकर : जब माननीय सदस्य पंजाब के सिंचाई मंत्री थे, तो उनके ज़माने में भी कुछ नालियां खोदी गई होंगी । मैं आज भी दिखला सकता हूं कि पंजाब सरकार की तरफ से जो नालियां खोदी गई हैं, उन में दिल्ली की साइड पर मिट्टी नहीं डाली गई है और पंजाब की साइड पर मिट्टी डाल दी गई है । इस कारण जब नालियों का पानी ऊंचा होता है, तो वह दिल्ली की तरफ आ जाता है ।

आज क्या हो रहा है ? कोई पहाड़ पर थोड़े ही बारिश हुई है ? पंजाब का पानी आया नाला नम्बर 8 में । उसमें दरार डाल दी गई और जमुना में पानी भर गया । इससे दिल्ली वाले परेशान हैं और तबाह हो रहे हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : दिल्ली और पंजाब के पापों से राजस्थान डूब गया ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि वे बीच में रुकावट न डालें ।

श्री नवल प्रभाकर : इस तरह का सिलसिला बन्द होना चाहिए । हम सब इस देश के निवासी हैं और हम सब को मिल कर इस समस्या को हल करना चाहिए । पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये चार इलाके ऐसे हैं, जहां के लोग—हम लोग—एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि हम दोषारोपण करना छोड़ कर मिल कर बैठें, इस समस्या पर विचार करें और फ़ैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि एक दूसरे की तबाही बन्द हो जाये ।

देश में बाढ़ सब जगह आती है, लेकिन पानी दो, तीन, पांच, सात दिन में निकल

[श्री नवल प्रभाकर]

जाता है । लेकिन मेरी कांस्टिट्युएन्सी की हालत यह है कि हर साल पानी आता है, लेकिन वह महीनों तक नहीं निकलता है । बरसात खत्म हो जाती है, सर्दी आ जाती है, सारे देश में बुआई होने लग जाती है लेकिन मेरी कास्टीट्युएंसी की अवस्था यह होती है कि पंजाब का पानी सर्दी में भी छोड़ दिया जाता है, जिससे खेत डूबने लगते हैं और जो थोड़ी बहुत बुआई की जाती है, वह भी तबाह हो जाती है ।

पिछली बार सर्दियों में, जनवरी के महीने में, पंजाब का पानी, काले रंग का और मैला, यकायक आ गया ।

श्री त्यागी : मैला ?

श्री नवल प्रभाकर : काले रंग का । (*Interruption*) मैं यह नहीं कह सकता कि पंजाब के कारनामे कैसे हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वह पानी ऐसा था कि जिसमें मछलियां मरी हुई थीं । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह दूषित पानी छोड़ दिया गया और हमारे यहां सारे नजफगढ़ ब्लाक में वह पानी फैल गया । मैंने डा० के० एल० राव को बताया कि आप जो मोरियां खोल रहे हैं, उनकी वजह से मेरी कांस्टीट्युएन्सी के लोग बहुत परेशान हैं ।

जब बाढ़ का प्रकोप होता है, तो वह कुछ वरदान भी साथ लाता है । बाढ़ अपने साथ बहुत सारा कूड़ा-कर्कट और खाद आदि लाती है, जो कि उपज को बढ़ाने वाले होते हैं । लेकिन दिल्ली की परेशानी यह है कि बाढ़ आती है, तो पानी महीनों निकलने का नाम नहीं लेता है । आज एक, डेढ़ महीने से नजफगढ़ ब्लाक में पानी आया हुआ है । नावें चल रही हैं, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं लेता है । पिछले शुक्रवार को बारिश आई, तब नौ इंच पानी कम था । लेकिन अगले दिन, शनिवार को, नौ इंच से पानी ऊपर चढ़ गया । हर खेत में छः, सात, दस फुट तक पानी खड़ा हुआ है । किसान लोग यह जानना चाहते हैं कि उन के यहां से पानी कब तक आप निकाल देंगे, कब तक पानी निकालने की व्यवस्था आप कर देंगे? उनकी यह मांग थी कि उन के यहां से पानी पंद्रह अक्तूबर तक निकल जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि आप उनकी इस मांग को पूरा कर देंगे ।

नजफगढ़ नाले के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह अंग्रेजों की देन है । यहां पर पानी कुछ बरसता है । नजफगढ़ नाले में मछलियां मारने का काम होता है । अंग्रेज चाहते थे कि यहां पर पानी बना रहे और उन्होंने कभी भी इस नाले को सफा नहीं कराया । ऐसा उन्होंने जानबूझ कर किया क्योंकि वे मुर्गाबियां वगैरह मारा करते थे । लेकिन 1947 के बाद ...

श्री बागड़ी : आदमी तो नहीं मारते थे ।

श्री नवल प्रभाकर : हमें स्वतंत्र हुए सतरह वर्ष हो गये हैं 1954 से लेकर आज तक पानी 1964 तक लगातार पानी आता है, लगातार पानी इस में बढ़ता जाता है, लगातार इस पानी के कारण परेशानियां बढ़ती गई हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि इसके बारे में कोई यत्न नहीं किया गया है । प्रयत्न किये गये हैं। लेकिन वे प्रयत्न एक दम असफल रहे हैं दिल्ली सरकार ने पहले यह कहा कि हम पानी इसका निकालेंगे लेकिन वह इस में कामयाब नहीं हो सकी। फिर सोचा गया कि भारत सेवक समाज इस पानी को निकालेगा और इसके कार्यकर्ता गये और उन्होंने निकालने की भी कोशिश की लेकिन उन को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई ...

श्री बागड़ी : चांदी वाला सोने वाला बन गया ।

Mr. Chairman: May I know whether the hon. Members are thinking loudly or are giving certain suggestions?

श्री नवल प्रभाकर : उसके कुछ कार्यकर्ता आए, कुछ ठेकेदार आये लेकिन उनको भी सफलता प्राप्त नहीं हुई ।

श्री बागड़ी : मैं कह रहा हूं कि दस साल के अन्दर कुछ किया नहीं है और वह कह रहे हैं कि किया है ।

सभापति महोदय : बीच में टोकना अच्छा नहीं है। मैं आप से इसके बारे में प्रार्थना कर चुका हूं।

श्री नवल प्रभाकर : फिर 1956 में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूजी ने उस इलाके को जा कर देखा और देखने के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिस में केन्द्रीय सरकार के बड़े बड़े इंजीनियर्ज थे, चीफ कमिश्नर थे और कुछ लोग जो इस मामले को समझ रखते थे, वे थे। जहां तक मुझे याद है लगभग दो करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया गया था । इस काम को केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । लेकिन केन्द्रीय सरकार को भी उसमें सफलता नहीं मिली । फिर मालूम हुआ कि यह इंसान के बस की बात नहीं है । कहा गया कि अब मशीनों के आर्डर दिये जायें । दो बरस तक मशीनें नहीं आईं और पानी इसी तरह से परेशानी का बायस बना रहा । अब जब मशीनें आ गई हैं तो कहा जाता है कि मशीनें कम हैं । नजफगढ़ नाले को आज इतनी क्षमता नहीं रही है कि वह इस सारे पानी को निकाल सके। यह नाला पानी निकाल देगा यह ठीक है । लेकिन बीच बीच में जो अप्स एंड डाउन्ज आये हैं उनको साफ करना बहुत जरूरी है । जब तक वे साफ नहीं होंगे यह पानी नहीं निकलेगा ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेरो कांस्टिट्यूएंसी की पचास हजार एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है । दिल्ली के दूसरे इलाके भी इसी प्रकार से पानी में डूबे हुए हैं। उत्तरी दिल्ली में भी इतनी ही जमीन पानी में डूबी हुई है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सत्तर गांवों में से पचास गांव पानी में डूबे हुए हैं । मैं मानता हूं कि हमारे राव साहब ने बहुत प्रयत्न किया है । उन से पहले जो मंत्रीगण थे वे यहां पर अपने दफ्तरों में बैठ कर के हुकम ही चलाया करते थे । लेकिन राव साहब स्वयं इंजीनियर हैं, वह समझदार व्यक्ति हैं, उन के मन में लगन है, तड़प है, और उन्होंने इस मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली है । इतनी उन्होंने इस मामले में रुचि ली है कि कि हर चौथे पांचवें या आठवें दिन वह जाया करते थे और जा कर एरियाज को देख कर आया करते थे। किन्तु जो दुखी लोग होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं, उनका जो दुख और परेशानी है वह जब तक दूर नहीं हो जाती है तब तक उनको सन्तोष नहीं मिल सकता है । मैं चाहता हूं कि उनके दुख का निवारण जल्दी से जल्दी हो ।

एक और प्रश्न है जो रोज हमारे सामने आ खड़ा होता है । पीने का पानी हमें नजफगढ़ नाले की वजह से स्वच्छ नहीं मिल पाता है, दूषित पानी हमें पीने के लिए मिलता है । इसके निवारण के लिए भी एक प्रोपोजल डा० राव साहब ने रखी है जिस में यह कहा गया है कि जनफगढ़ झील से पानी ले जा कर के अलग से पलवल के रास्ते जमुना के अन्दर डाल दिया जाए। अगर इस तरह से हो जाए तो न पानी दिल्ली शहर में आएगा और न किसी कालोनी में आएगा और न किसी को किसी किस्म का खतरा होगा । न किसी फैक्ट्री को कोई नुक्सान होगा और न किसी दूसरे को कोई परेशानी होगी । न गांवों में पानी फैलेगा, न पंजाब में पानी फैलेगा न दिल्ली में रहेगा । मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि आगे

[श्री नवल प्रभाकर]

आने वाले साल के अन्दर यह कठिनाई और परेशानी पैदा न हो ।

रिलीफ का जो काम हो रहा है, वह मुझे कुछ जंचा नहीं है । आज सुबह मेरा एक सवाल था जिस के उत्तर में बताया गया कि प्रत्येक परिवार को सौ सौ रुपये दिया जाएगा आप देखें कि क्या यह काफी है ? खरीफ की फसल हुई तक नहीं और रबी की फसल की कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है छः महीने के अन्दर वे लोग क्या करेंगे और क्या खायेंगे ? किस तरह से वे अपना गुजर बसर करेंगे ? कैसे अपने पशुओं को वे खिला पायेंगे मैं निवेदन करना चहता हूं कि कम से कम पांच सौ रुपये प्रति परिवार दिया जाना चाहिये । उस परिवार को जिस परिवार के पांच सदस्य हों । पांच सदस्यों से अगर अधिक सदस्य हों तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पचास रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिये ।

मकान भी गिर गये हैं । गांवों के जो गरीब लोग हैं उनके मकानों की यह दशा है कि पानी में वे बिल्कुल तबाह हो गये हैं,बरबाद हो गये हैं, मकान उनके टूट फूट गये हैं । उनके मकान बनाने का भी इंतजाम किया जाना चाहिये । चारा जो पशुओं का है, वह चारा भी दिया जाना चाहिये, उसका भी इंतजाम किय जाना चाहिये ।

माननीय राव साहब ने जितनी दिलचस्पी अब तक इस मामले में ली है, उसके लिए मैं उन की प्रशंसा करता हूं । मैं समझता हूं कि आगे वे इस से भी अधिक इस मामले में दिलचस्पी लेंगे, ताकि यह पंजाब, दिल्ली राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हर साल संकट आता है, वह टल सके और दिल्ली के पास आ कर जो पानी खड़ा हो जाता है, वह खड़ा न हो सके ।

श्री रामेश्वरा नन्द :

आदित्य हिरण्मयेन् पात्रेन् सत्यस्या पिहितम्,मुखम्

तत्वम् पूषंन् अपावृणु, सत्य धर्माय दृष्टये ।।

सभापति महोदया, यह बाढ़ का जो प्रश्न है, यह आज से नहीं अपितु जब से हमारा शासन आया है, तब से हमेशा ही हमारे सामने रहा है । बहुत से गांवों में तो पन्द्रह पन्द्रह वर्ष हो चुके हैं कि फसलें बिल्कुल हुई ही नहीं हैं । मैं इस बिवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं कि पानी कहां से आया, कैसे आया, रोहतक से आया, करनाल से आया, पंजाब से आया, दिल्ली सूबा डूबा या नहीं डूबा । मैं ने पढ़ा था कि दिल्ली में 38 इंच वर्षा हुई है, दिल्ली और इसके आसपास इतनी वर्षा हुई है । क्या यह वर्षा भी दिल्ली को पंजाब ने भेज दी है ? अगर वर्षा कहीं अधिक हो जाए तो क्या किया जाए ? क्या इस में भी किसी दूसरे प्रान्त का अपराध है ?

हम ने शास्त्रों में पढ़ा है, कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि क्यों होती है । वहां लिखा हुआ है :

अतिवृष्टि अनावृष्टि मूसक : सलभः शुकः
अत्यासन्नाच राजान् षडेता इत्यः स्मृतः ।

इस तरह की जो आपत्तियां हैं ये तब आती हैं जब शासन अत्याचारी होता है, अन्याय करने लग जाता है । तब अधिक वर्षा भी होती है, कम वर्षा भी होती है और अकाल भी पड़ते हैं । जो भाई यह कहते हैं कि साहब यह शासन क्या करे, तो मैं भी उन से ही यह पूछता हूं कि वह क्या करे, जब शासन बाढ़ों की रोक थाम नहीं कर सकता है तो करे क्या? शासन ने जो भूलें की हैं वे इसको नहीं करनी चाहिये थीं । जो भूलें की हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

अभी चकबन्दी हुई है । चकबन्दी से पहले पानी जहां से जाया करता था वहां कुछ प्रभावशाली लोगों ने, उन रास्तों को रुकवाकर नए रास्ते बनवा दिये, कुछ सड़कें निकल गईं, पुल ही नहीं लगाये गये और दिल्ली सूबे और हरियाणा को डुबाने का जो सब से बड़ा कारण है , वह कारण है, भाखड़ा बांध । पहले पानी अम्बाले से निकल कर करनाल और रोहतक से होता हुआ पश्चिम की तरफ जाया करता था और उधर से वह पानी आगे पाकिस्तान में निकल जाता था । लेकिन भाखड़ा बना, नहरें पक्की बनीं और इस कारण से पानी उधर से जाना बन्द हो गया । इसको आप बिल्कुल जा कर देख सकते हैं । और उसके नीचे से साइफन निकाला नहीं है । या अगर निकाला है तो बहुत छोटा निकाला है । इसलिये हरियाना को बचाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उस नहर के नीचे से, जहां से पानी आ कर जोर करता है, साइफन निकाला जाये ।

दूसरे, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं नदियों के बारे में, आप यमुना को ही ले लें, यमुना से सब नदियों का पता आप को चल जायेगा । यमुना का स्तर भूमि के स्तर के समान ही है, वह अधिक गहरी नहीं है, जब पानी ऊपर से आता है तो वह फैल कर चलता है । यमुना में कोई ऐसी जगह नहीं है जो पानी को सम्भाल ले । इलाके से पानी आता है नदियों के द्वारा और यमुना भी अपने में पानी ले कर आती है । इन नदियों के द्वारा इस इलाके में पानी फैलता है बजाय इसके कि यमुना उसे ले जा सके । इसलिये मैंने गत वर्ष श्री के० एल० राव से नम्र निवेदन किया था कि वे अपने कुछ उच्चाधिकारियों को भेजें । मैंने उन को तीन चार गांव दिखलाये । अभी श्री नवल प्रभाकर कह रहे थे कि वे बड़े दुखी हैं कि दिल्ली सूबे में और नजफगढ़ में इस प्रकार की स्थिति है । परन्तु वे दिल्ली के पास हैं, उन्हें दूरबीन लगा कर देखा जा सकता है, मिनिस्टर भी जा सकते हैं । लेकिन मैं करनाल की स्थिति आप के सामने रखना चाहता हूं । एक तरफ यमुना माई हैं, दूसरी तरफ मार्कन्डा है । उनके बीचों बीच नहर निकाली हुई है पानी के लिये, और सैकड़ों छोटी मोटी नदियां हैं उस क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर इस तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो करनाल तथा रोहतक और उस से सम्बंधित जितना भी गुड़गांव का भाग है और दिल्ली सूबा है, यह सही है कि कुछ दिन के पश्चात वह झील बन जायेगा और कई लाख जनता के लिये अभी से कोई स्थान निश्चित कर लेना चाहिये ।

हालत यह है कि अभी तक पानी मकानों में घुसा हुआ है । आप चल कर देख लें । गत वर्ष आठ गांव थे जो दिखलाने थे, लेकिन श्री के० एल० राव के उच्चाधिकारी केवल चार देख सके, जो कि यमुना के तट पर थे । वे आधे आधे बह गये थे । इस बार भी दो गांव बिल्कुल बह गये यमुना में और लोग बाहर पड़े हैं । उन को सरकार की तरफ से केवल 50 सिर्की मात्र दी गई हैं, और कोई चीज नहीं दी गई । पशु मरने लगे हैं, मकान बह गये हैं । वे जिस बुरी अवस्था में हैं, मैं नहीं कह सकता कि कोई मनुष्य उस अवस्था में रह सकता है । मैंने आपके वक्तव्य को पढ़ा । उस में करनाल की बात नाम मात्र है । मालूम नहीं होता कि करनाल में भी कोई बाढ़ आई है । अभी जितना रोहतक से लगता हुआ जो भाग है, जो करनाल की तहसील है पानीपत, उस को चल कर आप देख लें । मैं कहता हूं कि छः महीनों तक भी पानीपत तहसील के अहर, कोराना, कल्याना, और पट्टी आदि गांवों का पानी सूखेगा नहीं । यह स्थिति करनाल की है । मैं कहना चाहता हूं कि इस का कोई उपाय ढोन चाहिये । आप इंजीनियर्स को लगाते हैं, मैं मानता हूं कि आप के इंजीनीअर्स है, लेकिन वह दिल्ली के ठंडे कमरों में बैठ कर

[श्री राजेश्वरानन्द]

नक्शे बनाने वाले इंजीनियर हैं। आप देहात के लोगों से भी पूछ कर देखिये कि हम उस पानी को किस तरह से वहां से निकालें। लेकिन उन की तरफ आप का ध्यान नहीं है। जिस को अंग्रेजी टर्र टर्र नहीं आती, उस की बात को आप सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं। मैं आप से विश्वासपूर्वक कहता हूं कि इस समय हजारों पशु भूखों मर चुके हैं करनाल में। यही रोहतक की स्थिति है क्योंकि वहां तो पशुओं के लिये चारा तक नहीं है। मनुष्य तो इधर उधर भी जा सकता है। लेकिन पशुओं को कौन लेगा, जिन का 15 या 20 मन का बोझ होता है। धरती भी उन का भार नहीं सम्भालती। घास सब नष्ट हो गई है। हमने वक्तव्य में पढ़ा कि उन के लिये चारा भेजा गया है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आप बतलायें अगर आप ने करनाल में एक छटांक भी चारा भेजा हो। आप तो लाखों रुपयों की सहायता देते हैं। मैं नहीं चाहता आप देहातियों की आदत को बिगाड़ें लाखों रुपयों की सहायता दे कर। हम केवल यह चाहते हैं कि रुपया न दे कर आप इन नदियों का पानी किसी तरह से सफाई कर के निकालें। अगर आप ऐसा कर सकें तो अच्छा है। हमारी एक यही मांग है। अगर आप को सहायता देनी है तो रुपये मत दीजिये, रुपये से काम नहीं चलता उस क्षेत्र में जहां की बात मैं कह रहा हूं। इन क्षेत्रों में पिछले चौमासे में वर्षा हुई और अन्न नहीं हुआ। पिछली वर्षा के कारण इस साल फसल भी नहीं हुई और मैं विश्वास-पूर्वक कहता हूं कि इस समय सैकड़ों घर ऐसे हैं जिन में एक वक्त चूल्हा जलता है, अन्न का इतना अभाव है। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो वस्त्र दें, अनाज दें, आप उन को चारा दें। और भी यदि आप कुछ कर सकते हैं तो केवल एक काम करें कि हमारे पानी का कोई प्रबंध करें। यही मैं आप से चाहता हूं। भविष्य में इस के लिये हमें आप के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। इस में पार्टी का कोई प्रश्न नहीं। हम सब इस देश के रहने वाले हैं। लेकिन आज कोई पंजाब को दोष देता है और कोई किसी और को देता है। इस का एक बढ़िया हल मैं बतलाता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में एक ही सरकार रहे, सारी प्रादेशिक सरकारों को खत्म कर दिया जाये। तब किसी के लिये दोष देने का मौका नहीं रह जायेगा। परन्तु बटन दबाते समय जब उधर से बटन दबाये जायेंगे तो मेरा प्रस्ताव कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसका एक यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कब तक हम एक दूसरे को कहते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप के सामने कोई दूसरा उपाय हमारी समस्याओं का है। हम आप को श्रमदान देने के लिये तैयार हैं अगर जिन नदियों को हम बतलायें उन को आप कुछ थोड़ा सा गहरा करवा दें। मैंने डिप्टी कमिश्नर करनाल से बात की। मैंने कहा कि यहां से बांध लगवाइये और थोड़ा सा रेता एक फर्लांग में निकलवा दें तो पानी सीधा चलने लगेगा और कई गांव जो हैं वे नष्ट नहीं होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुझे से क्या कहते हैं कि स्वामी जी दरिया के प्रवाह को कौन रोक सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं रोका जा सकता है। क्या वह सोच कर चलता है, कोई प्रोग्राम बना कर चलता है। लेकिन इस सरकार की गद्दियों पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिधर से दबाब पड़ता है उधर हो लिया करते हैं।

16.26 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जिन नदियों की स्थिति बन गई है वहां आप अवश्य ही ऐसा कर सकते हैं कि वहां से रेता निकलवा दें। अगर आप ऐसा कर दें तो ताजेवाला से दिल्ली तक आप को कई हजार नहीं लाखों एकड़ भूमि, कई झील का खादर बोवाई के लिये मिलेगा। साथ में जहां पर रेता पड़ेगा उस जगह पर पेड़ लगाये जा सकते हैं और देश की और भी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प कुछ करने के मूड में हैं, आप की यह स्थिति है कि आप वस्तुत: कुछ करना चाहते हैं तो आप इस को अपने हाथ में लें, नहीं तो इतने खेत और दसियों गांव बह गये हैं और लगभग दस और आ रहे हैं । सम्भव है कि अगले चुनाव तक वह भी ह जायें । कौन जाने जब अब तक आप लोगों को बसा नहीं सके हैं तो इन लोगों को बसाने के लिये आप जगह न दे सकें । उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही है । मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि बिना पार्टी का ध्यान किये हुए, बिना किसी पार्टी का विश्लेषण किये हुए, इस समय देश की जनता जिस संकट में है, उस संकट को ध्यान में रखते हुए, इस तरह से की जाये तभी उन का कोई उपाय हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के मुताल्लिक जो रिपोर्ट हमारे मिनिस्टर साहब ने दी है उस में जहां तक फिगर्स का ताल्लुक है, कुछ कमी वेशी हो सकती है । हमारे मिनिस्टर साहब काफी अच्छे इंजीनियर हैं । आज मेरे मन में एक बात आई थी और असल में उस का जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तीसरे सफे में जो आखिरी पैरा है उस में किया है, और ज्यादातर ध्यान इस तरफ ही देने की जरूरत है । इस में दो चीजों की कमी जरूर नजर आ रही है । एक तो वह कमी जिसका मुजाहिरा अभी हमारे इस हाउस में हो रहा था कि कोआर्डिनेशन नहीं है । हम अलाहदा अलाहदा प्रदेशों की बात करते हैं, इस बात को नहीं समझते कि :

जो डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे,
न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे ।

यानी इस में किसी के बचने की आशा नहीं है । उन्होंने ड्रेन नं० 8 का जिक्र किया हमारे दिल्ली के मेम्बर ने । वह तो हमारी जान लेने लगा था । हमारी किश्ती उस में उलट गई । मैं तो कहूंगा कि जहां माननीय मंत्री ने 60 जानों का नुक्सान बतलाया है वहां शायद उन को 68 बतलाना पड़ता अगर हम आठ भी मर जाते । और मेरी किश्ती तो डाइवर्शन में उल्टी है, ड्रेन में नहीं । डाइवर्शन में पानी इतने जोर से चल रहा था । तो एक यह बात है कोआर्डिनेशन की ।

दूसरी बात वक्त पर मुनासिब इन्तिजाम का न होना है । हमारे पंजाब के जो इरीगेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में इस बात का इजहार किया है कि ये जो फ्लड हैं यह कोई नई बात नहीं है । सन् 1955 से मुतवातिर फ्लड आते रहे हैं । वैसे सन् 1947 में भी कहीं कहीं थोड़ी बाढ़ आती रही है । स्वामी जी ने सरकार पर इल्जाम लगाया है कि सरकार के कर्मों का फल कि सरकार शायद अच्छी तरह से सेवा नहीं करती इसलिये बाढ़ आ रही है । मैं समझता हूं कि हम में ही कुछ नुक्स हैं । हमारे सन्त महात्माओं के कर्मों का ही कुछ नुक्स है जिसकी वजह से हमारा इन्तिजाम ठीक नहीं होता ।

मैं अमृतसर से आता हूं । अमृतसर का जिला अनाज पैदा करने में बहुत मशहूर है । अमृतसर का किसान बार्डर तक खेती करता है, एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ता । वह अपने कन्धे पर बन्दूक रख कर बार्डर तक खेती करने जाता है । लेकिन आज बिल्कुल उलटा हो गया है । हमने खुद देखा है । मैं शुरू से इस कांस्टीट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूं । शुरू में उनकी मांग थी कि हमें खेती के लिये पानी नहीं मिलता, लेकिन आज हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि इस पानी को यहां से उठाओ, यह हमारी जान लेने वाला है । आज यह हो रहा है कि एक तरफ तो आप देश में जंगल काट कर खेती के लायक जमीन तैयार करते हैं और दूसरी तरफ जो जमीन हमारे किसान ने बनायी थी वह वाटर लागिंग की वजह से बिल्कुल

[श्री गु० सि० मुसाफिर]

बेकार हो गई है। और लोगों को परेशानी है। अमृतसर का जिला जो कि पंजाब का सबसे ज्यादा पैदा करने वाला जिला था उसकी हालत ठीक नहीं है। वहां की हालत हमें मजबूर करती है कि पंजाब की तरफ खास तवज्जह दी जाए। अगर इन छोटी छोटी बातों का खयाल कर लिया जाए तो यह इलाका अनाज पैदा करने में बहुत मुफीद हो सकता है।

जब भी हम जाते हैं तो हम से शिकायत की जाती है कि इस बार ड्रेन की खुदाई वक्त पर नहीं हुई। इसलिये हमारी सारी फसलें तबाह हो गई हर साल यही शिकायत की जाती है कि ड्रैन की खुदाई अच्छी तरह से नहीं हुई। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी एफीशेंसी बहुत कम है। मैं समझता हूं कि यह हमारे देश पर एक धब्बा है, एक दाग है कि हमारे पास ऐसे इंजिनियर और एक्सपर्ट नहीं हैं जो कि इन छोटी छोटी बातों को ठीक कर सकें ताकि बाढ़ें जो आती हैं व अधिक नुकसान न कर सकें। अगर इन बातों की तरफ वक्त पर ध्यान दिया जाये तो हम इन रोज रोज की शिकायतों को खत्म कर सकते हैं।

यह ठीक है कि आज पंजाब के 22 हजार गांवों में से चार हजार गांव डूबे हुए हैं पानी में। पंजाब में इस फ्लड से पहले ही 25 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसको अगर थोड़ा सा खोदा जाए तो उसमें पानी निकलने लगता है। वह खेती के लिये बेकार हो चुकी है वाटर लागिंग की वजह से और पहले के फ्लड्स की वजह से। इस फ्लड की वजह से पांच लाख एकड़ और जमीन पानी के अन्दर है। इसमें फसल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

मेरे दिल्ली वाले भाई ने कहा कि पंजाब की वजह से दिल्ली डूब गई, इसी तरह से पंजाब वाले भी शिकायत कर सकते हैं कि राजस्थान की वजह से पंजाब डूब गया, और राजस्थान वाले भी शिकायत कर सकते हैं कि यू० पी० की वजह से उनको नुकसान हुआ। यू० पी० से हमारे यहां लोग आए थे जो इस तरह पानी को बंद करना चाहते थे कि पंजाब का ज्यादा फायदा न हो और उत्तर प्रदेश को नुकसान न हो। लेकिन मैं तो किसी को इल्जाम नहीं देता और न इल्जाम देना चाहिये। इस बात के लिये हमारे इरीगेशन के मिनिस्टर साहब जज बैठे हैं। जो बात है वह उनके सामने है, और वह उसको देखते भी हैं। वह खुद इन बातों में इंटरेस्ट भी लेते हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि यह सिलसिला पैदा ही न होने देना चाहिये जिससे कि यह नुकसान हो। इस तरह ऐसी तवज्जह देनी चाहिये कि यह नुकसान बार बार न हो। इससे हर साल तबाही हो जाती है और हर साल यही शिकायत रहती है कि फलां काम वक्त पर नहीं किया गया इससे तबाही हो गई।

अमृतसर में हम ने खुद भी लोगों से सरविस करायी है। ड्रेनें वगैरह खुदवायी हैं, काफी काम करवाया है। फिर भी जो शिकायत आती है वह यही आती है कि वक्त पर काम नहीं हुआ। जैसे ड्रेन की खुदाई होनी चाहिये थी नहीं हुई। कहा जाता है कि इसी लिए यह पानी आ गया और तबाही और बरबादी हो गई।

वक्त खत्म हो रहा है। इस मजमून के साथ इतने वक्त में इन्साफ करना मुश्किल है। हमारे पास फिगर हैं कि हर साल मुतवातिर कितना कुछ सरकार करती रही है, मगर किसान को कभी तसल्ली नहीं हुई इस वास्ते कि एक दफ़ा उसने जो तकावी और कर्जा लिया उसको वह चुका नहीं सका और वह नए सिरे से डिसप्लेस हो

गया । इसलिये उसकी मुसीबत उसी तरह बनी रहती है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से दो बातें जरूर कहूंगा उनकी तरफ ध्यान दें । आखिर इस बात का क्या मतलब है कि हर साल यह शिकायत होती है कि वक्त पर काम नहीं हो सका और ठीक ढंग से नहीं हुआ । जिस वक्त तक यह बात दूर नहीं होंगी उस वक्त तक हम चाहे कुदरत का कितना ही गिला करें, हम जिम्मेवारी से बच नहीं सकते । दूसरे मुल्क वालों ने आसमान में नए चांद तक चढ़ा दिये । हम हिन्दुस्तान में यह तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या यहां हमारे इंजिनियर और एक्सपर्ट यह भी नहीं कर सकते कि जिस इलाके में बाढ़ आती है उस पर खास तवज्जह दे कर वक्त पर काम कर दें ।

दूसरे जो आपने कोआरडिनेशन कमेटी बनायी है उसको आप अमली शक्ल दें । सिर्फ कमेटी बना देना काफी नहीं है बल्कि इस पर जोर दें कि कोआरडिनेशन इस ढंग से हो कि न पंजाब को दिल्ली से, न दिल्ली को राजस्थान से और न राजस्थान को उत्तर प्रदेश से शिकायत रहे । इस तरीके से काम चलाया जाएगा तो मेरा खयाल है कि मुकम्मल तौर से यह सिलसिला खत्म हो सकेगा । बाकी कुदरत के साथ तो किसी का मुकाबला नहीं हो सकता । मगर जितना इन्सान कर सकता है वह तो हमको कर देना चाहिये । आज लोग हम से बदजन हो रहे हैं, और जब हम उनको तसल्ली देने जाते हैं तो वे समझते हैं कि हमें जीने की तसल्ली देने नहीं आए हैं बल्कि हमें आसानी से मरने भी नहीं देते । इस पर मुझे एक शेर याद आ गया :

तसल्ली दी गई उनको जिन्हें
दुश्वार जीना था
गरज यह थी कि मरना भी
उन्हें दुश्वार हो जाये ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी कहा गया कि प्रायः हर साल बाढ़ मारे देश में आ जाया करती है और हर दफे हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि पिछली बार जो काम होने थे वे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी स्कीम्स के लिए तो रुपया उपलब्ध नहीं है और छोटी स्कीम्स पर तब तक कोई काम शुरू नहीं होता जब तक कि जून का महीना नहीं आ जाता । हमारे कागजात के इधर से उधर जाने में ही न मालूम कितना समय नष्ट हो जाता है लेकिन काम वास्तविक तौर से कुछ भी नहीं हो पाता है और स्थिति जहां की तहां वैसे की वैसी ही बनी रहती है । जब बाढ़ आई उस वक्त कुछ दौड़ भाग शुरू हो जाती है । यह बिल्कुल सही बात है कि जितना नुकसान होता है उस का एक अंश मात्र ही सरकारी रिपोर्टों में आता है । पानी आया, घर बरबाद हुए, मवेशी मरे, आदमियों की जानें गईं और सब कुछ हुआ, उस के बाद भी हम लोगों को यह राहत नहीं मिल पाती है कि जो वास्तविक उन का नुकसान हुआ है उसी के अनुसार उन्हें छूट दी जाये । हालत तो यह है कि जितने ही बात की जाय लेकिन वसूली उसी प्रकार होती रही है । कहीं कहीं थोड़े दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है । अब जहां 12 आने नुकसान हुआ है वहां 6 आने या 7 आने कह कर उस में कोई राहत होने का सवाल है ही नहीं रखा जाता है । हालत तो यहां तक होती है कि चारों ओर पानी भरा रहता है और लोग अपनी रोज की जरूरियात के लिये बाहर नहीं जा सकते हैं, स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती हैं ।

[श्री श० ना० चतुर्वेदी]

कुएं जो हैं उन का पानी खराब हो गया। फसलें सड़ गईं खेत में खड़ खड़े और उनमें तमाम कीड़े, मकोड़ों की उत्पत्ति हो गई। वह जो फसल खड़ी हुई है उस को जानवर भी नहीं खा सकते। एक भयंकर दृश्य उपस्थित हो जाता है। मकान सोजन की वजह से बैठते हैं, बीमारी फैलती है और जब हालत बेकाबू हो जाती है तब इन से कहा जाता है कि आप श्रमदान कीजिये। यह कहां तक न्यायसंगत बात है? पहले पांच, पांच मील के ड्रेंस के लिए कहा गया था कि श्रमदान के जरिये यह बनाये जायेंगे लेकिन अब उसे घटा कर एक मील का कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो गलत काम होते हैं उन के ऊपर कभी किसी को सजा नहीं मिलती है। मेरी सूचना तो यह है कि ढांसा बांध के बनाने में बुनियादी गलती हुई है। इसी तरह से मुझे अपने आगरे के ड्रेंस के बारे में भी अनुभव है कि वहां पर भी इनको उलटा बनाया गया है। आगरा में बादरपुर ड्रेन ऐटा को छोड़ा गया जो आउटफौल से लेकर ऊपर को सोर्स की तरफ से बनाना चाहिए था लेकिन हुआ इसका उलटा है। आखिर यह उलटे ड्रेंस क्यों बनाये जाते हैं? इस में किस का लाभ है? नियम तो यह है कि आउटफौल पहले बना दिया जाये ताकि पानी का निकास हो जाये। मुझे नहीं मालूम कि आज तक किसी इंजीनियर को उसके ऊपर सजा मिली है। मंत्री महोदय स्वयं इस बात को जानते हैं कि एक दो नहीं बल्कि अनेक ऐसे केसेज मिलेंगे जिसमें कि ऐसा उलटा काम किया गया है। मैंने तो यह एक दो मिसाल दिये हैं। परिणाम यह होता है कि तमाम देहातों में पानी फैल जाता है और फसल को बर्बाद करता है। मेरी सूचना है कि ढासा बांध और नजफगढ़ के ड्रेंस से हुई तबाही भी ऐसी गलतियों का परिणाम है।

हमारी नदियों में सिल्टिंग हो रही और उन की ड्रेजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कोई साइंस की कला नहीं है जो दुनिया को मालम नहीं होगी। उन नदियों की आप ड्रेजिंग करें, बड़ी बड़ी नदियों का निकास देखें।

दूसरी शिकायत पुल-पुलियों के बारे में आती है। रेलवे लाइन बन गई, नहर बन गई लेकिन उसके नीचे से जो निकासी थी पानी, की वह रुक गई। जो यह पुलिया पड़ी है उस वजह से तमाम पानी भरा हुआ है और मांग की जाती है कि किसी तरीके से उन नहरों, आप हमारा पीछा छुड़ाइये। नहरों से सड़कों व रेलवे लाइन पर जो ड्रेनेज की पुलियां बनती हैं उनकी काफी चौड़ाई नहीं होती है। वह पानी को रोकती हैं उनको वहां चौड़ा किया जाये। आखिर इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं,

क्या वे इतना भी नहीं कर सकते कि पानी का इतना निकास हो जाए । मंत्री महोदय एक योग्य आदमी हैं, और इस काम को जानते और समझते हैं इसलिये जहां पर आप को जानबूझ कर कोई गलती की गयी मालूम दे तो ठेकेदार को आप कदापि न बख्शिये । जहां भी आपको शिथिलता और गफलत बर्ती जाती दिखाई पड़े वहां आप किसी को छोड़िये मत । जनता के सामने यह बात आती है, एक दफे नहीं बीसियों दफे सामने आती है और हमको भी मालूम होता है । हम कहते हैं कि साहब मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई । हमने यह कहा कि फलड्स आ रहे हैं जरा जाकर देखिये तो लेकिन अधिकारियों को चिन्ता नहीं रहती है । गांव वाले कहते हैं कि पानी का निकास उधर है लेकिन ड्रेन बिलकुल उल्टे अपोजिट डाइरैक्शन में बनाई गई है । वहां पर कहते हैं कि आप जाकर देखिये कि वाकई जो देहात वाले कहते हैं वह सही है या जो आपके इंजीनियर्स लोग दावा करते हैं वह बात सही है लेकिन बात वहीं की वहीं पड़ी हुई है । एक-एक नाले को चार, चार चक्कर कटवाये जाते हैं सीधा ड्रेन आये तब तो वह पानी ले सकता है ।

इसी तरह से मेरा कहना है कि बाढ़ पीड़ित किसानों में किसी को 15 रुपये और किसी को 20 रुपये दिया जाना इस मुसीबत में उनका घोर अपमान करना है । इस तरह की छोटी, छोटी सहायता देकर एक तरीके से हम उन्हें लज्जित करते हैं और वास्तविक रूप से उनकी सहायता नहीं करते हैं । मैं कहता हूं कि अगर सरकार यह चाहती है कि दरअसल उनको कुछ राहत मिले तो जितना भी बाढ़ आदि से नुकसान हुआ है उसकी बिलकुल सही-सही रिपोर्ट आनी चाहिये और कम से कम तब तक के लिये उन से जो मालगुजारी वगैरह वसूल की जाती है वह स्थगित हो जानी चाहिये । अगर आप वास्तव में उनको कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप उन्हें वह सहायता दीजिये जिस का कि वह कुछ उपयोग भी कर सकें । इस तरह से नाम मात्र की सहायता देने से कोई काम नहीं होने वाला है । सही बात होने के लिये और ताकि मालूम हो कि हमारी गवर्नमैंट को वास्तव में जो मुसीबत आई है, उस में उनकी सहानुभूति है और वह कोरी कागजी कार्यवाही नहीं दिखलाना चाहती है, सरकार को सक्रिय रूप से उनकी ठोस सहायता करने की व्यवस्था करनी चाहिए । दुःख की बात तो यह है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं वे एक अजीब दृश्य उपस्थित कर देते हैं, जिस वक्त उन के ऊपर मुसीबत आती है तो वे अधिकारी जरा भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कम से कम और कुछ न कर सके तो सही सही चीज तो अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा दें । ऐसे संकट के अवसरों पर भी उनका वही रवैया रहता है जैसा कि साधारणतया होता है । हमारे माननीय मंत्री एक योग्य व्यक्ति हैं, वे इस समस्या को खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं, उन में लगन व उत्साह है और मैं कहूंगा कि वे इस बात को देखें कि उन के इंजीनियर्स ठीक से काम करें । इसके अलावा जो उन मुसीबत जदा किसानों को सहायता आदि सरकार की ओर से दी जाती है वह ऐसी हो जिस से कि उनको वास्तविक लाभ मिल सके ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): श्रीमन् काफ़ी देर से इस बाढ़ पर हो रही बहस को सुन रहा हूं । दरअसल यह जो दिक्कत है यह गाड गिवन नहीं है बल्कि यह मैन मेड है । इंसान की ग़लती से यह चीज हुई है । अगर इन्सान अक्लमंदी से काम करे तो यह दिक्कत दूर हो सकती है । आज जो हमारे

[श्री यशपाल सिंह]

16.52 hrs.

करोड़ों आदमी बाढ़ से प्रभावित हैं वे सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार इंतजाम नहीं कर सकी है । यूरोप वालों ने दरिया राइन को बांध कर डाल दिया है, उनके हुकम में वह चलती है । लेकिन हमारे देश की दरियाएं बिना नकेल के ऊंट की तरह से चलती हैं । सरकार ने एक दिन भी यह कोशिश नहीं की कि उन दरयाओं को गहरा किया जाय । जापान के लोग भूकम्प से परेशान थे । उन्होंने इसका इंतजाम कर लिया है । उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है, कि ऐसी खोजें कर ली हैं कि भूकम्प आने से एक घंटा पहले चुम्बक पत्थर लोहे को खींचना बंद कर देता है । उन को एक घंटा पहले पता लग जाता है कि अर्थ-क्वैक आने वाला है और वे मकानों से बाहर आ जाते हैं । सरकार इन 17 सालों में सिर्फ इतना कर सकी है कि यह बाढ़ें और बढ़ गई हैं । बारिशें पहले भी होतीं थीं । बल्कि इस से ज्यादा होती थीं । बाढ़ का जो मूल कारण है और इस बारे में जो बुनियादी ग़लती हुई है, उस की तरफ़ सरकार का ध्यान नहीं गया है ।

हमारे देश में सत्तर करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है, जो कि कल्टीवेबल लैंड कही जाती है । उस ज़मीन को टिल करने के लिए सिर्फ ढाई करोड़ हल रखे गये हैं और सिर्फ पच्चीस लाख ट्रैक्टर हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्तर करोड़ एकड़ ज़मीन इन से टिल नहीं की जा सकती है । जो ज़मीनें पहले टिल की जाती थीं, वे पानी को पीती रहती थीं और पानी बाहर नहीं निकलता था । अब इस देश की करोड़ों एकड़ ज़मीन ऐसी है कि उस में हल और ट्रैक्टर नहीं चल सकता । वह ज़मीन बंजर हो गई है । इस लिऐ पानी पड़ता है और बाहर चला जाता है, दरया बन गए हैं, यही कारण है कि ज़िला रोहतक में 250 मुरब्बा मील के इलाके में किश्तियां चल रही हैं और वहां पर इन्सान इन्सान को नहीं देख सकता है ।

हम ने शुरू में कहा था कि बन-सम्पति को मत कटवाओ । हम ने कहा था कि बागात और जंगलात को मत कटवाओ । करोड़ों पेड़ हमारी मर्जी के खिलाफ कटवाए गए । पहले गंगा का पानी करोड़ों पेड़ों में रिस रिस कर जाता था । डा० के० एल० राव बड़े इंजीनियर हैं । मेरा ताल्लुक भी रुड़की यूनीवर्सिटी के साथ है । हम लोगों को यह पढ़ाया गया कि एक तिनका डेढ़ मन पानी को हरकत को रोकता है । पहले तो करोड़ों पेड़ थे, वे पानी की हरकत को रोकते थे । इसलिए बलिया, ग़ाज़ीपुर और देवरिया में पानी तीन महीने के बाद पहुंच पाता था । आज हालत यह है कि आज हरिद्वार और देहरादून में बारिश होती है तो और वह बारिश 48 घंटे में कहां कहां मार करती है ।

16.52 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

बन-सम्पति के नष्ट करने से बाढ़ें बढ़ी । दूसरे मुल्कों ने बाढ़ों को इस तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया । उन लोगों ने इंतिज़ाम किया है । कांग्रेस सरकार इंतज़ाम नहीं कर सकी है । आज भी अगर कल्टीवेबल लैंड्ज को बाकायदा, ठीक वक्त पर, जोता जाये, उन की ठीक टिलिंग हो तो कोई वजह नहीं है कि यह पानी इस तरह से बिखरा या फिरे ।

दिल्ली के मुट्ठी भर लोगों को हिफाजत के लिए ढांसा बांध बना कर रोहतक की उस जनता को मारा गया है, जो छः फीट के जवान पैदा करती है । हिसार की उस जनता को मारा गया है, जहां के जवान नेफा और लद्दाख के मोर्चों

पर लड़ते हैं । उस जनता को डुबो कर मारा गया है । आज वहां पर 250 मुरब्बा मील इलाका ऐसा पड़ा हुआ है, जहां पानी के सिवाय कोई चीज नहीं दिखाई देती है ।

सरकार चाहे, तो आज भी इस का इन्तजाम कर सकती है, लेकिन सरकार इस का इन्तजाम नहीं करना चाहती है । जब दिल्ली की शिकायत की जाती है, तो कहा जाता है कि दिल्ली में जगह की इतनी कमी है कि एक चारपाई पर दो आदमी सोते हैं । लेकिन हमारे किसानों, और छोटे जमींदारों की हालत देखिए । हमारा किसान भैंस के साथ सोता है । हमारा किसान बैल के साथ सोता है । उस को हर वक्त यह खतरा रहता है कि कहीं रात को बैल उस की छाती पर पैर न रख दे और उस की जिन्दगी की लीला समाप्त न हो जाये । लेकिन दिल्ली की हालत को सुधारने के लिए उन लोगों को डुबो कर मारा गया है, जो कि देश के लिए गल्ला पैदा करते थे, जो देश के लिए फतहयाबी हासिल करते थे । यह सरकार का पाप है और सरकार को इस का प्रायश्चित करना पड़ेगा । अगर सरकार प्रायश्चित नहीं करेगी, तो हालत और भी खराब हो जायेगी, यह देश और रोहतक, हिसार का इलाका झील की हालत में होगा ।

ब्रिटिश पीरियड को हम गैर-मुल्की राज कहते थे । हम उस के खिलाफ बगावत करते थे । हम उस के खिलाफ लड़ कर जेलखानों में जाते थे, लेकिन एक दिन हम ने नहीं देखा था कि बाढ़ की इतनी मुसीबतें आती हैं । जब आये साल मुसीबत आती है, तो क्यों नहीं मंत्री जी उस का इन्तजाम करते ? आये साल वही हालत होती है । हमारे जिले, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर सब इस लिए पीछे रह गए हैं कि वे डूबे पड़े हुए रहे । उन बेचारों की हालत यह हो गई है कि वहां सिर्फ सर्दियों में चार महीने खाना बनता है । बरसात में वे डूबे पड़े रहते हैं । गर्मियों में हालत यह है कि उन को यह डर रहता है कि कहीं उन के झोंपड़ों में आग न लग जाये । इस लिए वे खाना नहीं बना सकते । अगर सरकार चाहे, तो इस का इन्तजाम कर सकती है । ये मैटीरियलिज्म के जो पुजारी हैं, उन के लिए मैं कह रहा हूं । उन्हें इन्तजाम करना जरूरी है । जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उन का इन्तजाम भगवान खुद करते हैं । गीता माता में यह आज्ञा हुई है,

अनन्याश्चिंत अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः
पर्युपासते ।।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।

गीता में यह हुक्म हुआ है कि मैं अपने शरणार्थी, प्रेमी और भक्त की हर चिन्ता अपने ऊपर ले लेता हूं । लेकिन जो मैटीरियलिज्म के पुजारी हैं, मैं उन के सामने चार सुझाव रखना चाहता हूं ।

जो दरया बिना नकेल के ऊंट की तरह बह रहे हैं, उन को गहरा करना पड़ेगा । जो जमीनें अनटिल्ड पड़ी रहती हैं, वे बाढ़ का कारण होती हैं । उन अनटिल्ड लैंड्ज का इन्तजाम करना पड़ेगा । ट्रैक्टर्ज और पशुधन को बढ़ाना पड़ेगा । इस के अतिरिक्त वन-सम्पत्ति पैदा करनी पड़ेगी । आज बागात और जंगलात खत्म हो गए हैं । दोबारा वृक्षारोपण कर के और वन-महोत्सव आयोजित कर के जंगलात को बढ़ाना पड़ेगा । सब से जरूरी बात यह है कि जिस इलाके की बाढ़ का इन्तजाम नहीं हो सका, वहां के मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और मुन्तजिम लोगों को यक-कलम बरखास्त कर दिया

[श्री यशपाल सिंह]

जाये । ये मैन-मेड दिक्कतें हैं—ये गाड-गिवन दिक्कतें नहीं हैं । इन का हल हो सकता है ।

मैं ने ये सुझाव इस लिए रखे हैं कि आज जो करोड़ों आदमी डूबे हुए पड़े हैं, उन के रहन-सहन का इन्तजाम हो सके । सरकार एक दफा कह दे कि हम इन्तजाम नहीं कर सकते । आज कौन मरता है ? कोई राय बहादुर, खान बहादुर, रायजादा या कोई राजा-महाराजा नहीं मरता है । गरीब, किसान और मजदूर मरते हैं । चाहे यहां बाढ़ आए, चाहे बाढ़ आये बलिया में और चाहे गोरखपुर में, किसान मरता है मजदूर मरता है, जो गरीब आदमी है वह मरता है—बड़ा आदमी नहीं मरता है । "यहां बिजली गिरे या उस चमन में आंधियाँ आवें, वहर सूरत गरीबों का ही घर बर्बाद होता है । इन मिनिस्टरों और बड़े बड़े लोगों को यह पता नहीं है कि बाढ़ कितना सत्यानाश कर रही है । सरकार बाढ़ की समस्या को हल करने के सिलसिले में कोई डेफिनेट डेट दे । इन लोगों ने दुनिया में मेटीरियलिज्म का इतना बोल बाला कर रखा है । ये लोग मेटीरियलिज्म की परस्तिश करते हैं । जितना रुपया इन्होंने मेटीरियलिज्म के लिए खर्च किया है, अगर उस का एक-चौथाई रुपया इन्होंने स्पिर्चुअलिज्म के लिए खर्च किया होता, तो भगवान खुद इन की इमदाद करते । चूंकि ये भगवान से बिमुख हुए, इस लिए इन के हाथ-पैर बेकार हो गए है ।

दूसरे देशों ने दरियाओं को बांधा है । दूसरे देशों ने करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा की है । दूसरे देशों ने अपने रेगिस्तानों को चीर कर चमन खड़ किये हैं । लेकिन कांग्रेस सरकार बेकार के कामों में, नाच-गाने, ड्रामों , रंगीनियों, कल्चरल प्रोग्राम्ज में रुपया बहाती रही और उस ने किसान और मजदूर के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया । जो भगवान को मानते हैं, उन के लिए इस बात की जरूरत नहीं है, जो कि मैं उन लोगों को कह रहा हूं, जो कि मैटीरियलिज्म के पुजारी हैं । कुरान पाक में यह हुकम हुआ है :

कुल इन्न सलाती वनुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहे रब्बिल आ मीन ।

जो अपनी जिन्दगी और मौत को खुदा के हवाले कर देता है, उस शख्स पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ ती है ।

श्री बृज राज सिंह–कोटा (झालावाड़): हजरत ईसा ने क्या कहा है, वह भी बता दें ।

श्री यशपाल सिंह : सरकार के लिए यह जरूरी है कि ...

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त बहाव है । इस वक्त किसी को नहीं बोलना चाहिए ।

श्री यशपाल सिंह ...वह बैलों और ट्रैक्टरों का इन्तजाम करे, जंगलात को बढ़ाने का इन्तजाम करे, ताकि देश आगे बढ़े ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी फ्लड की तरह ही चल रहे थे ।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): My I request that Members from all States may be given opportunity to participate in this debate.

Mr. Speaker: I will certainly try to do that. But a little more time should be given to Members coming from flood-affected areas. In any case, every Member should try to be brief. Now, Shri Gajraj Singh Rao.

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव): जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं । फ्लड्ज की वजह से जो तबाही और

बरबादी हुई है, उस के बारे में तमाम मेम्बर साहबान फ़रमा चुके हैं ग्रौर इसमें किसी को भी शक नहीं है। सवाल यह है कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब ग्रौर दूसरी स्टेट्स मुश्तर्का तौर पर यह सोचें कि क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज है या नहीं। राजस्थान, दिल्ली ग्रौर पंजाब के रोहतक ग्रौर गुड़गांव ज़िलों में जो फ्लड्ज़ ग्राए, साहबी नदी उन का कारण है। मैं ने पिछले मार्च में इर्रिगशन ग्रौर पावर के मुताल्लिक बोलते हुए यह कहा था कि साहबी नदी पर छोटे छोटे बांध नहीं, बल्कि बिग एम्बैंकमेंट्स बनाए जायें। ग्रगर तीन एम्बकमेंट्स गुड़गांव ज़िले में, तीन राजस्थान में ग्रौर एक दिल्ली में बनाए जायं, तो वह पानी इस्तेमाल हो सकता है। गुड़गांव ज़िले की रीवाड़ी तहसील के लोग सरकार के बहुत मशकूर होंगे, क्योंकि वह खारी रकबा है ग्रौर वहां पर पानी पीने को नहीं मिलता है। वह पानी वहा पर ग्राबपाशी के काम ग्रा सकता है ग्रौर यह फ्लड्ज़ का मसला भी दूर हो सकता है। ग्रपने तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूं कि —मैं ने इन बांधों का इन्तज़ाम किया है —कि यह तमाम फ्लडज़ बन्द हो सकते हैं। हुग्रा क्या? ढांसा बना दिया गया। ग्रनप्लान्ड तरीके पर एक बांध बना दिया गया। क्या कभी एक बांध भी हुग्रा करता है? मिनिस्टर साहब सब से बड़े इंजीनियर हैं। वह जानते हैं कि सिरीज़ ग्राफ़ बंद्ज़ हुग्रा करते हैं, जो कि मुसलसल तरीके से पानी की रोक-थाम कर के ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता उस की रफ्तार को भी कम करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ढांसा बांध से ग्रागे इंडस्ट्रियल एरिया में से नजफगढ़ ड्रेन ग्राता था। उन्होंने गंग से तमाम रोक दिया ग्रौर इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वह पानी तमाम नहीं निकल सका ग्रौर यह नज़फ़गढ़ नाला तबाही का वायस बना ग्रौर तमाम रोहतक, गुड़गाव में इसने तबाही मचाई। ये तमाम चीज़ें हैं जो ग्रापको माननी पड़ेंगी। हमारे राव साहब इंजीनियर हैं, इसके बारे में मैं उनको कनविंस करने के लिए तैयार हूं ग्रौर मुझे जब वह चाहें बुला लें ग्रौर मैं उनको कनविंस कर दंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक साहिबी पर सीरीज़ ग्राफ़ बांध नहीं होंगें तब तक यह साहिबी का पानी इसी तरह से तबाही मचाता रहेगा।

उजीना झील को भी ग्राप देखें, उसका भी ग्राप मुलाहिजा फरमायें। वहां जाने तक की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे स साहब एयर फ्ला ट कर के मेवात का इलाका देखने के लिए गये थे। वहां पानी ही पानी है। लंडोहा नदी जो राजस्थान में से ग्राती है, उसके तीन बांध बहुत खराब थे। वे तमाम टूट गए हैं। वह पानी उजीना में ग्राया। उजीना के पानी का निकास कामा लेक ग्रौर गोवर्धन ड्रेन में जाना था। लेकिन ग्राज तक गोवर्धन ड्रन दस बरस हो गए हैं, कागजों पर ही मौजूद है। वह नहीं बन सका है। राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सेंटर उनको देता नहीं है। इस में तीन चार स्टेट्स ग्राती हैं। जब तक यह मामला ठीक नहीं हो जात, जब तक गोवर्धन ड्रेन से ानी नहीं निकलता है, तब तक कुछ नहीं हो सकत. है।

17 hrs.

एक बात उसूलन में ग्रर्ज करना चाहता हूं। नैचुरल ड्रेन जो है, जो कुदरती पानी का बहाव है, उनको तब तक नहीं रोका जाना चाहिये जब क कोई सर पूरा पक्का इंतजाम नहीं हो जाता है। ग्र.पने बगैर प्ल के ढांस ब ा न लि ा । इसी तरह से उजीना बांध है जहां का पानी इस वक्त तक निकल जाना चाहिये था। ग्रब तक फसलें बोई जानी चाहिये थीं। लेकिन तजवीज किया गया है कि उसको बन्द कर दिया जाए, पानी न निकाला जाए। 621 फुट पर उजीना झील का पानी है। इसका नतीजा यह हुग्रा है कि यह फसल गई, रबी की ग्रगली फसल

[श्री गजराज सिंह राव]

तक पानी नहीं रोक सकेंगे और इससे न केवल देश को नुक्सान होगा, बल्कि लोगों को भी भारी मसीबत का सामना करना पड़ेगा ।

गोवर्धन ड्रेन अगर होता तो कुदरती पलो जो था उससे सारा पानी निकल जाता किसी इलाके में । यह क्यों नहीं हुआ, इसको राव साहब खुद जानते हैं । वह अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है । किस के जिम्मे था गोवर्धन ड्रेन को खोदना और उसने क्यों नहीं खोदा । वे कहते हैं, राजस्थान वाले कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था । उत्तर प्रदेश तक में तीन चार स्टेट्स के अलावा इससे तबाही आई है ।

यही चीज आप हर जगह पायेंगे कि अनप्लांड तरीके पर काम होता है । प्लांड तरीके पर नहीं होता है । कंस्ट्रक्टिव तरीके पर काम हो तो पानी का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है । आज उसका तबाही के तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है ।

जो रिलीफ दिया गया है उसको आप देखें तो पायेंगे कि एक रुपया फी आदमी भी नहीं पड़ता है । उन गांवों में जहां पानी ने जबर्दस्त तबाही मचाई है, आप गये भी नहीं हैं । वहां पर जाना कौन पसन्द करता है ? पानी में जाना कोई पसन्द नहीं करता है । असल गांवों में कोई नहीं गया है । वहां पर जो तबाही मची है उसका अनुमान तो देख कर ही लगाया जा सकता है । मैं अर्ज करुंगा कि इन बाढ़ों का मुस्तकिल तौर पर कोई इंतजाम किया जाना चाहिये । इस काम के लिए एक कमेटी बिठाई जानी चाहिये । लेकिन जब पानी निकल जाये तो आप यह न भूल जायें कि कोई कमेटी बिठाई गई थी । अगर कोई मुस्तकिल इन बाढ़ों का इंतजाम किया जाए तो तबाही से बचा जा सकता है चाहे वह तबाही असम में आती हो, दिल्ली में आती हो या और किसी प्रदेश में आती हो । तीन चार स्टेट्स का जब मामला था तो कभी अलवर का राजा नहीं मानता था, कभी दिल्ली वाले नहीं मानते थे । इस तरह से काम नहीं चल सकता है । श्री राव उनको बिठाये और जब तक इस मामले का मुस्तकिल हल न हो, तब तक उनको न छोड़ें ।

अध्यक्ष महोदय : अब हर एक माननीय सदस्य सात मिनट में खत्म करने की कोशिश करे ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : उत्तर प्रदेश और पंजाब वालों को तो बोलने का अवसर मिल रहा है लेकिन . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे रहें तो सब को समय मिल जायगा । जब तक सब को, जो कि बोलना चाहते हैं, मौका नहीं मिल जाता है, हम यहां से नहीं जायेंगे । अगर आप बैठे रहने के लिए तैयार हैं, तो सब को मौका मिल जाएगा ।

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Sir, on a point of information. May I know whether the Half-an-Hour discussion regarding strike in Sindri Fertilisers Factory will be taken up today or is it postponed? It was to start at 5-00 p.m. Am I getting that privilege today?

Mr. Speaker: About the Half-an-Hour discussion, I learnt in my chamber that the House had desired that might be postponed. He an just go and have his rest.

श्री तन सिंह (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस बाढ़ के सिलसिले में किसी भी प्रकार की आलोचना करना व्यर्थ है । जिस किसी भी भाषा में आलोचना की जाती है उस भाषा के शब्द और अर्थ इस सरकार के सामने अब व्यर्थ हो चुके हैं । सत्तरह साल से लगातार प्रतिवर्ष यह चीज यहां आती है, इसपर बहस होती है और बहस के बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है । जब यह एक सामान्य चीज हो गई है तो सरकार की आलोचना करना बेकार है ।

मैं तो सरकार को सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने शब्दकोष के कुछ शब्दों का अर्थ भी बदल दिया है । अब तक यह बाढ़ दैवी विपदा के रूप में थी लेकिन अब वह विपत्ति के रूप में नहीं रह गई है, वह सामान्य चीज़ हो गई है । म बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाढ़ आने पर क्या होता है । केवल इतना ही नहीं कि पानी भर जाता है, इस के अतिरिक्त एक नियमित रूप से चीज़ होती है, भाषणों की बाढ़ आती है, उस के बाद मंत्रियों के दौरों की बाढ़ आती है, उस के बाद आश्वासनों की बाढ़ आती है और नियमित रूप से जो कार्यक्रम होते हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : बाद में तकरीरों की बाढ़ आती है ।

श्री तन सिंह : यही मैं ने कहा है । इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भाषण देने का कष्ट क्यों मोल लेना चाहिये । यह एक नियमित चीज़ हो गई है, आवश्यक चीज़ हो गई है और इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने हम को अब मजबूत बना दिया है, चाहे जितनी बाढ़ आये, इस देश के नागरिक अब इस बात के लिए तैयार हो गये हैं कि उस को वे सहन कर लें । सहन करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं रह गया है । मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि गवर्नमेंट विल डू एव्री-थिंग पासिबल । लेकिन अब इन शब्दों का भी कोई अर्थ नहीं रह गया है । इन शब्दों को सहन करते-करते इस सरकार को भी लोग सहन करने के लिये तैयार हो गये हैं । सिवाय सहन के और कोई चारा भी तो नहीं है ।

हम स्वतंत्र हुए । स्वतंत्र होने के पश्चात् इतना तकनीकी विकास हुआ कि कोई ठिकाना ही नहीं और इस के बारे में बहुत सी बातें भी कही जाती हैं । लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें हर साल इस विपत्ति का सामना करना पड़ता है । परस्पर विचारों का मतैक्य न हो, परस्पर कोई मत भेद हो, तब भी बात समझ में आ सकती है । लेकिन जब सभी मानते हैं कि इन बाढ़ों का सामना करना चाहिये, इन से छुटकारा पाने का यत्न किया जाना चाहिये और सरकार स्वयं भी इस विषय में जागरूक है, तो क्या कारण है कि इन पर आज तक काबू नहीं पाया जा सका है । मंत्री महोदय सज्जन प्रकृति के हैं । जब मैं उन की आलोचना करता हूं तो मुझे खेद होता है । मैं तो समझता हूं कि सारे का सारा जो प्लानिंग है यह कहीं न कहीं गड़बड़ा गया है । जो योजना कमिशन बैठा हुआ है और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में बहुत बढ़चढ़ कर प्रचार करता है जब वह कहता है कि हम देश के अन्दर बहुत अच्छी नियामत लाने वाले हैं तो समझ में नहीं आता है कि वह कमिशन इन बाढ़ों के विषय में क्या कर रहा है । यदि उस का दृष्टिकोण केवल एकपक्षीय है कि बांध बना दिये जायें, नहरें खुदवा दी जायें, तो मैं कहूंगा कि उन की अदूरदर्शिता इस हद तक पहुंच गई है कि वह सोच भी नहीं सकता है कि बाढ़ें भी आ सकती हैं, दैवी विपत्तियां भी आ सकती हैं और उन के सम्बन्ध में क्या किया जाय ? यदि यह एक पक्ष योजना कमिशन का बिल्कुल अधूरा है तो मैं खेद से कहूंगा कि वास्तव में कोई योजना ही नहीं है । तकनीकी विकास के प्रति जो जनता का विश्वास है वह भी धीरे धीरे उठता जायगा । हम जानते हैं कि पहले भी बाढ़ें आती थीं, दैवी विपत्तियां आती थीं और उन को सहन करने के सिवा लोगों के पास कोई चारा नहीं होता था लेकिन आज हम भाषणों के सिवाय कोई चारा नहीं पाते हैं । इस से अधिक और क्या कहा जाय । कितनी गम्भीरतापूर्वक, कितनी निष्ठापूर्वक हम इस बात को कहें कि हम नहीं चाहते हैं कि बार-बार यह बात यहां लायें, बार बार इस बात को कहने और सुनने

[श्री तन सिंह]

का अवसर आयें । हम चाहते हैं कि सरकार आखिरी रूप से फैसला कर ले, देश की बाढ़ों को हमेशा के लिए नियंत्रित कर ले अन्यथा योजना कमिशन को हटा दीजिये, बेकार में लोगों का यह जमघट बैठा रखा है, आप ने । इस से बेहतर तो वही लोग हैं जो कम से कम उस स्थान के रहने वाले हैं, जो समझते हैं कि पानी का बहाव किधर है, किधर जा रहा है, और किस तरह से उसे घटाया जा सकता है । इतने बड़े योग्य व्यक्तियों को योजना कमिशन में रक्खा जाता है लेकिन मैं नहीं जानता कि अपनी योग्यता को वे कब काम में लायेंगे । मैं बहुत देर से सुनता आ रहा हूं कि इस का प्रबन्ध होने वाला है । मैं थोड़े से समय में उदाहरण दूंगा राजस्थान की घग्घर नदी का । उस में हर साल बाढ़ आती है । वहां के लोगों को इस बात का अभ्यास हो गया है कि वहां वर्षा हुई नहीं कि बाढ़ आई । मैं आश्वासन भी बराबर सुनता आ रहा हूं कि इस पर इतने करोड़ रुपये मंजूर होने वाले हैं जिस से कि साइफन बनाया जायेगा और पानी को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जायेगा । लेकिन लगातार स्थिति वही बनी हुई है । हर साल हजारों लाखों रुपयों का नुक्सान होता है । सूरतगढ़ फार्म है । वह लगातार घाटे में जा रहा है । वह सरकार की अपनी मिलकियत है । जब उस के सम्बन्ध में सरकार को चिन्ता नहीं है तो जनता के सम्बन्ध में उसे क्या चिन्ता होगी, यह मैं नहीं जानता । जो एक सरकारी सूरतगढ़ फार्म बना हुआ है उस को हर साल इस बाढ़ का मुकाबला करना पड़ता है । पता नहीं सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने वाली है क्या नहीं । मैं चाहता हूं कि जब भविष्य में हम यहां आयें तो कुछ राहत मिले । ऐसी परिस्थिति न हो कि हम अपने को दैवी विपत्तियों से असुरक्षित अनुभव करें ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : इस सदन में फ्लड, फारेन अफेअर्स और फूड डिबेट हर बार होती है । तीनो समस्यायें अपनी जगह पर हल होने के बजाय उत्तरोत्तर गम्भीर होती जा रही हैं । फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है, अभी आप के योजना आयोग ने बतलाया कि ऐसा किया जायेगा । गंगा फ्लड कंट्रोल की बात की गई । लेकिन क्या कंट्रोल हुआ, यह कहीं पर देखने में नहीं आया । हमारे यहां उत्तर प्रदेश में खास कर गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया में हर साल फ्लड्स आते हैं और जनता दुखी होती है । अभी नाव का जिक्र आया । जब कभी फ्लड आया तो कमेटी बैठती है और यह विचार किया जाता है कि हर गांव में कम से कम एक नाव की व्यवस्था कर दी जाये, जिस में आधा रुपया सरकार दे और आधा रुपया गांव सभा दे । फ्लड् गया, नाव की व्यवस्था गई, फ्लड आया, व्यवस्था प्रारम्भ हुई । लेकिन नाव अभी तक नहीं बनी । कई बार यह सुझाव दिया गया कि गांव सभायें नाव आदि का खर्च दें । लेकिन उन के पास कोई सुरक्षित निधि नहीं है । अगर यह सम्भव हो तो धीरे-धीरे सरकार नाव बना दे और गांव सभाओं से आधा धन लेना ही हो तो ले ले, लेकिन नाव दे दे । लेकिन यह व्यवस्था अभी नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि एक योजना हुई थी गांवों को ऊंचा करने की हमारे प्रदेश में । काफी गांव कागज में ऊंचे किये गये, कुछ मौके पर भी लोग गये, करोड़ों रुपया इस पर व्यय किया गया । मगर गांव ऊंचे नहीं

हुए । घर कुछ ऊंचे जरूर हुए कहीं कहीं । किसी ने ओवरसियर को रुपया दे कर ठीक कर लिया तो उस का घर ऊंचा हो गया । हर्ष की बात है कि हमारे श्री राव वहां गये थे । उन्होंने गोरखपुर के गांवों को देखा, उन्होंने उन के घरों को ऊंचा करने की मंजूरी दे दी । लेकिन बीच बीच में वैसे ही गड्ढे पड़ हुए हैं । हम ने एक योजना बनाई गांवों को ऊंचा करने की बाढ़ से पहले गांव ऊंचे कर दिये जायें ।

एक माननीय सदस्य : आप के वहां होते हुए भी वहां पर लोग खा जाते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : ओवरसियर और सभापति सब खा जाया करते हैं । यह सब चल रहा है । इन्क्वायरी हो रही है । कई गांवों में मिट्टी नहीं पड़ी लेकिन गांव ऊंचे हो गये । आप ने हमारे सुझाव को माना । मैंने सुझाव दिया कि गांव ऊंचा करने के लिये विलेज रेजिंग एक्ट बनाया जाये जिस के आधार पर गांव ऊंचे किये जायें । और उन के चारों तरफ पोखरे बना दिये जायें तो मिट्टी मिलने में आसानी हो जायेगी । ज्यादा मिट्टी की ढलाई नहीं करनी पड़ेगी और गांव भी समतल हो जायेंगे । जहां जहां लोग गांवों में बसे हुए नहीं हैं उन को मजबूर किया जाये कि वे वहां आ कर बस जायें । वहां पर एक नाव दे दी जाय और मसला हल हो जायेगा । लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ । बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप ने आदेश दे दिया है कि इस आधार पर गोरखपुर में चार गांव ऊंचे किये जायें । मंत्री महोदय के जाने के बाद जून महीने में हमारे यहां इंजीनियर आये कि राव साहब का आदेश है गांवों को ऊंचा करने का और हम इस गांव को लेते हैं । हम ने कहा कि गांव जून में ऊंचा नहीं होगा । अगर गांव को ऊंचा होना है तो मार्च के पहले होना चाहिये जब कि पानी नहीं रहेगा । इसके बाद दूसरी बाढ़ बांधी लेकिन हाल बिगड़ता गया । मैं बतलाना चाहता हूं कि हर साल गोरखपुर में फ्लड नुक्सान पहुंचाता है । इस का कारण यह है कि खराब बांधे हुए बांधों में से करीब करीब एक तिहाई बांध टूट गये । उनके टूट जाने से पानी का फंसाव हो गया और बाढ़ की स्थिति इतनी विषम हो गई । जहां पर बांध बने थे वहां पर जब राव साहब गये थे तो देहाती लोगों ने उन से कहा कि साहब आप बांध बनाते जायेंगे और हम डूबते जायेंगे क्योंकि जितनी ओपेनिंग थी नदियों की वह बन्द कर दी गई है । उन को खुलवा दो, हमें बांधों की कोई जरूरत नहीं है । जितना भी बहाव था नदियों का सब बन्द कर दिया गया । उन नदियों को पुनः खोल दिया जाये । अगर और कुछ नहीं तो आप रेगुलेटर लगा दें तो भी बाढ़ का निराकरण हो सकता है ।

फ्लड कंट्रोल बोर्ड क्या करता है । केवल बांध को बांधने की योजना । मुझे स्मरण है कि यू० पी० की सरकार ने, जहां तक मेरी जानकारी है, इस सम्बंध में एक आयोग बनाया था । उस आयोग ने इस बात का फैसला किया कि बांध बांधना बाढ़ को रोकने का कोई हल नहीं है, लेकिन इस आयोग के फैसले के बाद भी बांधों का बनाना आरम्भ हो गया । बजाये रोकने के बनना शुरू हो गया । आप इस की जांच कर लें । उन्होंने कहा था कि बांध बनने नहीं चाहियें । आज कल बाढ़ आती है तो लोग दौरा करने के लिये तैयार हो जाते हैं । मेरा एक सुझाव है कि जब बाढ़ आये तो बाढ़ से घबराना नहीं चाहिये । बाढ़ के बीच में रहने वाले आदमी बाढ़ से घबराते नहीं हैं क्योंकि उस से मिट्टी अच्छी आती है । वे घबराते कब हैं, जब फसल का नुक्सान होता है, घर गिर जाते हैं । इसलिये गांवों को ऊंचा कर दिया जाये जिस में घर न गिरें । फसल के लिये कुछ व्यवस्था कर दी जाये । हमारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी

[श्री सिंहासन सिंह]

चाहिये ताकि किसान फसल पैदा कर ले। जितनी भी खरीफ की फसल होती है वह साठ या सत्तर दिनों में तैयार हो जाती है। अगर वह मई महीने में बो दी जाये तो वह तैयार हो जायेगी। प्रायः जुलाई या अगस्त में बाढ़ आती है। मई और जून में फसल इतनी आगे बढ़ जायेगी कि बाढ़ से उस को नुक्सान नहीं होगा। लेकिन अब तक इसके लिये कोई योजना नहीं है। लेकिन अभी तक इसके लिये कोई कार्यक्रम नहीं है। न कोई इरिगेशन की योजना है और न कोई पम्पिंग सेट्स की योजना है। ट्यूबवेल लग दें तो भी उनके खाने की समस्या हल हो सकती है। इससे नाव की समस्या भी हल हो जायेगी। देहात में रहने वाला बाढ़ का स्वागत करेगा क्योंकि उस की मिट्टी अच्छी होती है। आप इस पर विचार करें तो कम से कम हमारे क्षेत्र में इससे बड़ी राहत लोगों को होगी। अब जितने बांध बने हुए हैं उन से जितनी नदियों का बहाव रुकता है उन को ओपेन करें, सड़कों को ओपेन करें, जो नेचुरल बहाव है नदियों का उस से मिला दें, गांवों को कुछ ऊंचा करें, अर्ली क्रापिंग के लिये कुछ पानी का प्रबंध करें तो लोगों को कम से कम चना गेंहूं तो मिल सकेगा।

श्री लहरी सिंह : पंजाब स्टेट की आज हालत यह है कि जितने जिले हैं अमृतसर से ले कर दिल्ली बार्डर तक, उन का एक भारी हिस्सा आज पानी में डूबा हुआ है। मिनिस्टर साहब को मालूम है। यह बात नहीं कि यह उन को मालम नहीं है। जो स्टेट अनाज भी काफी पैदा करती थी, जहां मवेशी भी काफी होते थे, हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े बैल और भैंस जो मुहैया करती थी, आज आहिस्ता आहिस्ता स्टेट की तकसीम होने के बाद हालत खराब होती जा रही है। दो सालों से आहिस्ता आहिस्ता वहां के अनाज की पैदावार घटती चली जा रही है, वहां के मवेशी खत्म होते जा रहे हैं। अगर इस हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब स्टेट खत्म हुई समझिये।

मैं चन्द तजवीजें आप के सामने पेश कर दूं। जिस वक्त पंजाब की तकसीम हुई उस के पहले हमारे बहुत से ड्रेन्स पाकिस्तान के रक्बे में से गुजरते थे अब वह इलाका पाकिस्तान में आ गया और हमारा पानी निकलना बन्द हो गया। उन ड्रेन्स के बन्द होने से हमारे इलाके में पानी भरा हुआ है। और तकसीम के बाद उन ड्रेन्स के बदले में कोई ड्रेन्स का और सिस्टम नहीं बनाया गया। मेरी दरख्वास्त है कि जो हमको तकसीम की वजह से नुक्सान हुआ है और जो ड्रेन पाकिस्तान ने बन्द कर दिए हैं उनकी वजह से जो पानी जमा हो जाता है उसके निकालने का तो इंतिजाम किया जाए।

दूसरे पंजाब में नहरों से बहुत ज्यादा आबपाशी होती है। इनमें भाखरा नहर को छोड़ कर बाकी नहरें कच्ची हैं और उन से सीपेज की वजह से बहुत नुक्सान हो रहा है। मेरा सुझाव है कि जिन इलाकों में यह सीपेज होता है उन में सारे में अगर आप नहरें पक्की न कर सकें तो कुछ पैचेज में पक्की कर दें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर आपको वाके में पंजाब को बसाना है तो जहां आप और चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वहां एक सीपेज ड्रेन बना दीजिये। इसके न होने से वहां दो साल से कम अनाज पैदा हो रहा है। पंजाब का बैल मजबूत है, आदमी भी मेहनती है। लेकिन इस वाटर लागिंग की वजह से लाचार हो रहा है और इस वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है।

पंजाब की छोटी सी स्टेट है। वहां पांच हजार गांवों को पानी से नुक्सान हो चुका है। इसमें मिनिस्टर साहब का कुसूर नहीं है, प्लानिंग का कसूर है। पंजाब के लिए

पूरा रुपया नहीं रखा । प्लानिंग कमीशन समझती है कि ज्यादा पानी देने से और फ्लड कंट्रोल से ही ज्यादा अनाज पैदा हो जाएगा । लेकिन पंजाब में वाटर लागिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है । इस मामले में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब भी कंजूसी करते हैं । न उन्होंने पंजाब के लिए काफी रुपया एलाट किया और न ठीक प्लान बनायी गयी ।

आखिर में मैं हरियाने के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूं । दांसा बांध बनाया गया । मैं अर्ज करना चाहता कि हिन्दू राजाओं के जमाने से और मुगल काल से हमारे यहां का पानी और साहिबी नदी का पानी नजफगढ़ झील में आता रहा है । लेकिन झील के ड्रेन को चौड़ा नहीं किया गया इससे दिल्ली में पानी भरता है । आज उसके लिए तजवीज की जा रही है । मुझे शक है कि इस पर अब भी अमल होगा । जो दिल्ली में पानी आया उसमें हमारे आदमियों का कसूर नहीं है । आप देख सकते हैं कि हमारे यहां के पानी का नेचुरल फ्लो दिल्ली की तरफ को है लेकिन पंजाब को इसको बदलने के लिए मजबूर किया गया । इसी से दिल्ली में पानी भरता है । ड्रेन नम्बर 8 दिल्ली तक ठीक आता है लेकिन यहां उस का लेविल बढ़ा कर उसको दरिया में गिराने के लिए पंजाब सरकार को कहा गया । उसका नतीजा यह है कि जब दरिया में पानी बढ़ता है तो वापस लौटता है और दिल्ली में पानी बढ़ जाता है ।

मैं आखिर में फिर कहना चाहता हूं कि पंजाब की तरक्की के लिए पंजाब सरकार को ज्यादा रुपया मिलना चाहिए ।

Shri Liladhar Kotoki (Nowgong): Mr. Speaker, it is the fitness of things that the problem of floods. . . .

Mr. Speaker: There is no flood in Assam.

Shri Liladhar Kotoki: I shall come to it, Sir. But before that I want to join my friends from Punjab in urging the Minister to do all that is possible to remove the difficulties created by flood and water-logging in Punjab.

It is not true that there is no flood in Assam. The statement itself refers to floods in Assam. The statement that was laid on the Table of the House on the 7th September says on page 4:

> "The damage that has occurred so far and my inspection of the areas convinces me that a very thorough and competent organisation is immediately called for for the maintenance of flood embankments in Assam. The standards of maintenance have also to be immediately improved. As regards the erosion which has been the main cause for large-scale damage, it is necessary to find out economical methods of tackling this problem. These erosions shift from place to place and area to area. So they require continuous and constant investigation and study for effective control."

So, Sir. . . . (*Interruptions.*)

Mr. Speaker: The simultaneous translation apparatus should be switched off when it is not in use.

Shri S. M. Banerjee: It is a constant disturbance. . . . (*Interruptions*).

Shri Liladhar Kotoki: So, this shows that floods control measures so far taken in Assam have not had the desired effect.

In this connection, I would refer to the Report of the High Level Committee on Floods published in 1958 in which various recommendations were made for control of floods in Assam. I will only request the hon. Minister to just enquire whether measures so far taken conform to the recommendations made in the High Level Committee Report.

[Shri Liladhar Kotoki]

During his tour recently the hon. Minister observed that he realised the magnitude of the floods in Assam. I must express my gratitude to the hon. Minister for his suggestion last year to close the Kaiang river and its execution in a very speedy way which has saved the entire district of Nowgong including the Nowgong town. Similar measures ought to have been taken to save a large number of villages and towns that have now immersed in the Branmaputra and the Barak and their tributaries. Therefore, the question of erosion has posed today a more serious problems than the flood problem, which is serious as it is. I would urge the hon. Minister to apply his mind to tackle the problem of erosion which is eating away large areas in my State. I have no time to go into the figures and convince hon. Members of the colossal extent of the effects of erosion. Floods cause misery to the people for a short time but there are some beneficial results when the floods recede. So far as erosion is concerned, the damage is permanent. It eats away villages and towns; people are uprooted and they have to be rehabilitated elsewhere. It is a very difficult problem that has arisen in my State. The problem is also too big for a State like Assam to tackle. Therefore, my submission is, here is a case where the Centre must take the full responsibility of tackling the problem of flood and erosion caused by the Brahmaputra and the Barak.

In this connection, Sir, I would like to refer to the very right step that has been taken by the Government to tackle the problem of sea erosion caused to the coasts of Kerala. In that State it was found necessary to have the advice and services of international experts. So far as erosion caused by the mighty Brahmaputra is concerned, I submit, it will perhaps be necessary to requisition the services of international experts to advise the Central Government as to how to tackle this problem. It may also be necessary to get aid from other countries because it will we a very colossal programme.

Sir, I know my time is up. Therefore, while concluding I will again request the Minister to give his careful and earnest thought to salvage our State from the damages of flood and erosion.

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : अध्यक्ष महोदय, साल ब साल हम हाउस में बाढ़ की बहस रखते हैं और बाढ़ समस्या के बारे में विस्तार से अपने विचार प्रकट करते हैं। हम लोग अपनी तमाम बातें कह जाते हैं। उस के बाद सेक्रेटेरियट या मंत्री महोदय के विभाग से सम्बन्धित अधिकारी उस की बाबत एक रिपोर्ट तैयार कर के भेज देते हैं और उसी की बेसिस पर यह मिनिस्टर्स लोग यहां पर हमें जवाब दे देते हैं लेकिन उस से आगे हम नहीं बढ़ते हैं। नतीजा यह होता है कि जब हम लोग जनता में जाते हैं और जब हम से वहां पर पूछा जाता है कि गये साल में बाढ़ की रोक थाम के लिए सरकार की ओर से क्या किया गया है तो इस पर हमारा मुंह बंद हो जाता है और हम लोगों को कोई तसल्ली-बख्श जवाब नहीं दे पाते हैं। इस लिये मेरा कहना है कि अब यह बाढ़ के बारे में सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मिनिस्टरों द्वारा वही घिसा पिटा जवाब दुहराया जाना बंद होना चाहिए। बार बार वही फिगर्स उनके द्वारा देते जाना अब रुकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिये कि आखिर वह काम कितना आगे बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा और भविष्य के लिए उसका माकूल इलाज होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस के लिए ठोस क़दम उठायेंगे।

अभी एक अन्य साथी माननीय सदस्य ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। मैं भी मानता हूं कि बाढ़ का जितना बड़ा सवाल है उस से

कम बड़ा सवाल कटाव का नहीं है । बाढ़ से जो नुकसान होता है उस से ज्यादा नुकसान कटाव में होता है । इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचना चाहता हूं कि जितनी मुस्तैदी बाढ़ के सवाल को हल करने में लगाई जाय उतनी ही मुस्तैदी से कटाव के सवाल पर भी ध्यान दिया जाय । और उस के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह फीगर्स हम लोगों के सामने दी हैं उन के मुताबिक़ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा पंजाब व राजस्थान सभी प्रान्तों के सम्बन्ध में फलड डैमेज के बारे में एनफौरमेशन दी गई है । समय की कमी के कारण मैं सब का जिक्र इस समय अलग अलग करने में असमर्थ हूं लेकिन जो टोटल उन्होंने दिया है उस के बारे में कहना चाहूंगा । टोटल तो उन्होंने दे दिया है हालांकि बहुत सी जगहों में कोई फीगर्स नहीं दी गई हैं जैसे कि गुजरात के वास्ते लिख दिया गया है कि इन-फौरमेशन एवैटेड । जे० एंड के० के लिए लिख दिया है कि इनफौरमेशन एवैटेड । मद्रास के बारे में उन्होंने निल लिखा है । उड़ीसा के बारे में उन्होंने लिखा है कि इनफौरमेशन नौट रिसीव्ड । हिमाचल प्रदेश की बाबत भी लिखा है कि इनफौर-मेशन नौट रिसीव्ड । पौंडिचैरी के बारे में निल लिखा है । बाकी जो फीगर्स दी हैं उन में भी बहुत से आइटम्स उन्होंने कह दिया है कि आइटम्स नौट रिसीव्ड, निल । छोड़ दिये हैं और जो फिगर्स दिये भी हैं वे कम्प्लीट नहीं हैं । जो भी फीगर्स उन्होंने दिये हैं उस के आधार पर यह देखा जाय कि देश को कितना नुकसान बाढ़ से पहुंचा है, टोटल को अगर देखा जाय तो पता लगेगा कि टोटल एरिया एफैक्टैड 60.98 लाख एकड़ है । दूसरा टोटल नम्बर औफ़ विलैजेज़ अफैक्टैड 17991 बतलाये गये हैं । इसी तरह से टोटल पापुलेशन अफैक्टैड 65.92 लाख हैं । टोटल ऐरियाज डैमेज टु क्रौप्स में टोटल ऐरिया 29.85 लाख एकड़ है लेकिन जहां उसकी वैल्यू लगाने का सवाल है वह उन्होंने बड़ी आसानी से छोड़ दिया है और उस कौलम में उन्होंने लिख दिया है नौट ऐराइब्ड ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सारा समय तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने में ही निकला जा रहा है ।

श्री क० ना० तिवारी : बिहार के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं चम्पारन का रहने वाला हूं । चम्पारन, दरभंगा और नौर्थ बिहार के सभी जिले क़रीब क़रीब बाढ़ से पीड़ित होते हैं । बिहार में आपने अपने स्टैटमेंट में बतलाया है कि टोटल ऐरियाज एफैक्टैड 28.89 लाख एकड़ हैं । उस के नम्बर औफ विलैजेज की तादाद 4730 है । टोटल पापुलेशन एफैक्टैड 38.13 लाख है । डैमेज टु क्रौप्स का टोटल एरिया 12.49 लाख एकड़ है और उस डैमेज की वैल्यू 1710.24 लाख रूपये आंकी गई है । डैमेज टु हाउसेज की वैल्यु 40.23 लाख रुपये है । हैड्स औफ़ कैटिल लौस्ट 52 है और इसी तरह से और भी नुकसान के आंकड़े दिये गये हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन फीगर्स को देखने से मालूम हो जायगा कि बाढ़ से वहां पर कितनी क्षति होती है । हर साल हमारे यहां जितनी भद्र क्रौप है । जितना खाने का अनाज भादों में होता है वह सारे का सारा नष्ट हो जाता है । कटाव की वजह से हजारों आदमी बेघर हो जाते हैं । ईस्ट बंगाल से आये हुए रैफ्यूजीज़ को आप यहां पर बसाते हैं लेकिन हजारों आदमी जो बाढ़ और कटाव से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं उन को आप ज़मीन नहीं दे सकते हैं उनको घर बसाने के लिए भी ज़मीन नहीं

[श्री क० न० तिवारी]

दे सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बाढ़ से और कटाव से जो भी राहत आप बिहार को नौर्थ बिहार को दिला सकें वह दिलाने के बारे में उचित व आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे डा० के० एल० राव अपने विषय के बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन हमारे इतिहास की सम्भवतः उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। कुछ दिन हुए जब यह बयान दिया गया कि यह साहबी नदी अब की बार ही बहुत तूफ़ान कर चुकी है। मेरा निवेदन है कि साहबी नदी पिछले 50 वर्ष से जब से मैं ने होश सम्भाला है तब से हर पांचवें और सातवें वर्ष यह तबाही लाती है और यह तबाही न केवल राजस्थान में आती है बल्कि पंजाब में, जिला गुड़गांव और दिल्ली में भी आती है। जब से राजस्थान बना है तब से हमने यह प्रयास किया कि अलवर जिले में कम से कम एक बांध बांध दिया जाय लेकिन उस बांध को बांधने के लिए जो भी योजना बनी उस को इंकार कर दिया गया। पहले कहा गया कि इस में रेता आता है। उस के बाद कहा गया कि इस में 75 लाख रुपया लगेगा और उस का 4 प्रतिशत लाभ नहीं मिलता है। फिर कहा गया कि इस से एक बांध बनेगा जिस में नुकसान 20–25 हजार रुपये वार्षिक होगा लेकिन आज अकेले अलवर जिले में 50–60 लाख रुपये का नुकसान हो गया और जो तबाही पंजाब और दिल्ली में बचती वह तबाही भी हुई और करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हो गया। आज तक उस बांध के बारे में यह नहीं कह सके कि वह क्यों नहीं बांधा जा रहा है? मैंने कंसलटेटिव कमेटी में भी इसको कहा था तो ताया था कि इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी हम लेंगे। यह हालत जब बाढ़ के बारे में हो तो फिर क्या किया जा सकता है?

मुझ से पहले माननीय राव गजराज सिंह ने राजस्थान तीन बांधों की तामीर के लिये कहा है। मेरा तो कहना है कि तीन के बजाय अगर एक भी बांध बंध जाय तो भी बहुत कुछ काम हो सकता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यहां कुछ ऐसा मालूम होता है कि जो ज्यादा पुकार सकता है उस की ज्यादा सुनी जाती है। इस रिपोर्ट में भरतपुर के बारे में बहुत बड़ी बात कही गई है किन्तु मैं निवेदन करूं कि अलवर क्षेत्र में ज नुकसान हुआ है शायद कागजों में वह बहुत थोड़ा आये में अभी 26 तारीख को वहां से हो कर आया हूं और मैं ने देखा है कि वहां क़रीब 50 गांव ऐसे हैं जिनकी कि हालत यह हो गई है कि उनकी जमीनें समाप्त हो गई हैं और उन के कम से कम 2000 या 2500 घर नष्ट हो गये हैं और करीब 30 फ़ीसदी लोगों के पास शाम का खाना भी नहीं है। वहां पर यह दशा है कि 50 लाख रुपये का नुकसान केवल उसी जगह पर हो गया है, जब कि गवर्नमेंट के स्टेटमेंट में सारे राजस्थान में शायद 52 लाख रुपये का नुक्सान दिखाया गया है। जब कभी बाढ़ आती है, तो सरकारी अफ़सर इस कोशिश में रहते हैं कि कम से कम नुकसान दिखाया जाये, ताकि जनता को मालूम न हो जाये कि तबाही कितनी है। वहां यह हालत है कि अभी तक कुछ गांव नदी के पानी से भरे हुए हैं। वहां जीप नहीं जा सकती है। लोग पैदल जाते हैं। मैं स्वयं भी पैदल ही गया था।

इमदाद के बारे में पूछने पर कलैक्टर साहब ने कहा कि हम ने ऊपर लिख दिया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा, वह अभी तक कागजों पर ही है और कोई कार्यवाही

नहीं की गई है । बदनसीबी यह है कि मुझ से पहले एक एम० एल० ए० वहां पर पधारे, तो वहां का बी० डी० ओ० ताश खेलते मिला । जब मैं एम एल० ए० के साथ वहां गया, तो तीन बजे दफ्तर पर ताला लगा हुआ मिला और सब लोग ग़ायब थे । यह हालत उस सरकार की है, जो कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने का दम भरती है ।

जब वहां बाढ़ आई, तो मुझे देवयोग से यहां एक मिटिंग में जाना पड़ा । मेरे पीछे वहां के एस० डी० ओ० और कांग्रेस के एक नेता वहां पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति को भी अपना राजनीतिक साधन बनाया । उन्होंने इस प्रकार का ताना दिया कि विरोधी पक्ष के लोग इस वक्त क्यों नहीं आए । लेकिन जनता अब इतनी अनजान नहीं रही है और वह समझ चुकी है कि इस तरह की बात कहना अच्छी बात नहीं है । लोगों ने इस का कड़वा जबाब भी दिया ।

यदि साहबी नदी की समस्या को हल करना है, तो मुझ से पहले श्री गजराजसिंह राव ने जो सुझाव दिये हैं, वे बहुत ही ठोस सुझाव हैं; इसलिए उन पर अमल करना चाहिए ।

डा० राव महोदय ने जो को-आर्डिनेटिंग कमेटी बनाई है, वह केवल यह न देखे कि वर्तमान हालत क्या है, बल्कि वह इस समस्या को दूर तक देखने की कोशिश करे । इस कमेटी को केवल यही नहीं देखना चाहिये कि पानी कहां से आता है, बल्कि रेलवेज ने पुराने जमाने से जो हमारी हालत बिगाड़ी हुई है —ख़ास तौर पर से पटौडी के इलाके में तबाही ला दी है— जब तक यह कमेटी उस पर विचार कर के ऐसा कोई उपाय नहीं निकालेगी कि रेलवे लाइन के नीचे से पानी कैसे निकाला जाये, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

यह जो तरीका है कि बाढ़ आई और कह दिया कि हम कुछ देंगे, लेकिन रुपये में एक पैसा भी नहीं पहुंचता है, इससे कोई लाभ नहीं होता है । मेरा सुझाव है कि भारत सरकार सब सरकारों के समथ मिल कर किसी प्रकार एक फंड बनाए, ताकि बाढ़ का बीमा किया जाये और इस वक्त लोगों की जिन्दगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वह बन्द किया जाये । जब तक हम बाढ़ के बारे में बीमे की कोई योजना नहीं बनायेंग, तब तक ग़रीब लोगों के करोड़ों रुपयों का नुक्सान होता रहेगा । गांवों में जो तबाही आती है, वह ग़रीब पर आती है । अमीर का पक्का मकान तो बच जाता है । ग़रीब आदमी और हरिजन इत्यादि गांव से बाहर पड़े रहते हैं, और उन को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है । हमारे यहां यह दशा हो रही है कि खेत के लिए बीज नहीं हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चीजें ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है ।

श्री बडे (खारगोन) : रहने के लिए मकान नहीं है ।

श्री काशीराम गुप्त : मकान नहीं है । जब चट्टर के लिए कहा गया, तो जबाब मिला कि हम ने वहां भेजने के लिए कोटा मन्जूर कर दिया है और हम भारत सरकार से बाढ़ पीड़ितों के लिए अलहदा क्वोटा मांगेंगे । मैं समझता हूं कि जब वे लोग मर चुकेंगे और उन का दम निकल चुकेगा तब शायद वह कोटा वहां पहुंचेगा । उस से कोई लाभ नहीं होगा ।

बाढ़ की समस्या सारे देश की समस्या है, किन्तु जिन क्षेत्रों की यह विशेष समस्या है, उन में राजस्थान, पंजाब, यू० पी०, बिहार और दिल्ली इत्यादि आते हैं । सरकार को इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए, ताकि अगले वर्ष भी हम को यहां यही कथा सुनने को न मिले और हमें इस प्रकार के भाषण न देने पड़ें ।

Shri Bade: Please take not of crop insurance.

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, सन्त तुलसीदास ने कहा है :

ज्यों ज्यों सुरसा वदन बढ़ावा
तासु द्गुण कपि रूप दिखावा

बाढ़ रोकने की कोशिश जितनी ही की गयी बाढ़ उतनी ही बढ़ती जा रही है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह बाढ़-नियंत्रण विभाग है या बाढ़-नियंत्रण विभाग है—यह विभाग बाढ़ का नियंत्रण करता है या बाढ़ को निमंत्रण देता है । मैं अपने यहां की बात बताना चाहता हूं । हमारे यहां के लोगों का कहना है कि बाढ़ पहले तो एक दैवी विपत्ति थी । और अब वह सरकारी सृष्टि भी हो गई है सरकार की ग़लत योजना के कारण भी लोगों को बाढ़ का बहुत बुरा फल भोगना पड़ता है ।

मैं कोसी के पश्चिमी तट-बंध का जिक्र करना चाहता हूं । वहां आज हालत यह है, कि तट-बंध के अन्दर जितना पानी होता है तट-बंध के बाहर उस से ज्यादा पानी होता है । मेरा घर तट-बंध के अन्दर है । मैं दो तट-बंधों के अन्दर रहने वाला आदमी हूं, लेकिन तट-बंध के बाहर के लोग मेरे गांव में शरणार्थी बन कर आते हैं और जिन गांवों में कभी पानी नहीं जाता था, वहां की फसलें मारी जाती हैं । आज वहां पर यह दृश्य है । मैं डा० राव का ध्यान ख़ास तौर से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोसी के पश्चिमी तट-बंध न दर्जनों नदियों का मुंह बन्द कर दिया है । तिलजगा, घोरदा, पांची, पर्वता, खरक, धनजैया, वलान, गहुंआ आदि कई नदियों का मुंह बन्द कर दिया गया है । कितनी नदियों का नाम मैं गिनाऊं ? लेकिन इन नदियों के पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया ।

जो थोड़े स्लस-गेट बने, उन की अजीब हालत है । जब रिवर-साइट में, नदी की तरफ़, पानी कम होगा, तब तो गांव की तरफ़ से बांध के बाहर का पानी स्लूस होकर निकलेगा, अन्यथा पानी नहीं निकलेगा । पानी निकलने का रास्ता क्या होगा ? जिन नदियों में ख़ास कर के बालू आता है, उन की हालत यह होती है कि बालू के बराबर आते रहने से तट-बंध के भीतर बालू जमा होता है और तट-बंध के अन्दर का स्तर ऊंचा होता रहता है । इस प्रकार साल-ब-साल कम पानी आने पर भी वह दृश्य पैदा हो जाता है, जो कि बड़ी बाढ़ के समय होता है । 1954 में कोसी में सवा आठ लाख क्यूसिक पानी डिस्चार्ज हुआ था लेकिन अब दो तीन लाख क्यूसिक पानी के डिस्चार्ज होने पर भी वह दृश्य पैदा हो जाता है, जो सवा आठ लाख क्यूसिक पानी के डिस्चार्ज होने पर होता था ।

पिछले सात आठ बरसों में नदी में बालू जमा हो गया और तट-बंध के अन्दर ज़मीन का स्तर ऊंचा उठ गया । इसलिए प्रोटक्टिव बांध बनाने से पहले नदी के बालू की समस्या का भी अध्ययन किया जाये । कोसी बैराज का जीवन अनिश्चित है । उस के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो कोठार डैम बनाने की योजना थी, अभी उस का अनुसंधान चल रहा है । कोसी योजना पूरी हो गई, लेकिन उस को बचाने की योजना का अभी अनुसन्धान चल रहा है, जब कि दस बरसों में पूरी कोसी योजना के पूरे पैसे व्यर्थ हो जायेंगे, अरबों रुपये पानी में बह जायेंगे ।

डा० राव को अच्छी तरह पता है कि कुनौली और डलवा के नज़दीक तट-बंध को ख़तरा क्यों होता है । वह इंजीनियरों की ग़लती से होता है । अभी बैराज बना । बैराज हो कर पानी निकाला गया । उस को लम्बा रास्ता देना चाहिए था । लेकिन बहुत लम्बा रास्ता न दे कर चार मील के अन्दर उस पुरानी धारा में मिला दिया गया । जिस नदी में लाखों क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज होता है ।

उस नदी के बहाव को कुछ ही दूरी पर ले जा कर पुरानी नदी में गिरा दिया गया । आज हालत यह है कि एक साल में एक एक, डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपये उस तट-बंध की रक्षा के लिए खर्च किये जाते हैं । इस प्रकार अवैज्ञानिक योजना, अनसाइंटिफ़िक प्लानिंग से सरकार और इस देश का नुक्सान हो रहा है ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । कमला बलान का पूर्वी तट-बंध जयनगर से शुरू होता है और कोसी का पश्चिमी तट-बंध कुनौली से शुरू होता है । यहां दोनों की दूरी पचास मील के लगभग है । मधेपुर अंचल में आ कर, भेजा और भगवानपुर गांव के नजदीक आ कर, दोनों तट-बंधों की दूरी तीन मील के लगभग है । बीच में जहां रेलवे लाइन है वहां उसकी दूरी चौदह मील रह जाती है । मैं राव साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मधेपुर अंचल को भी बचाना चाहती है या नहीं ? वहां एक समुद्र जैसा दृश्य उपस्थित हो गया । एक तरफ रेलवे का बांध है दूसरी तरफ कोसी का पश्चिमी तट-बंध है और तीसरी तरफ कमला बलान का पूर्वी तट-बंध है और दोनों की दूरी तीन मील है । पचास मील के एरिया में से जो पानी आ जाता है उससे मधेपुर अंचल एक समुद्र जैसा बन जाता है और जिन गांवों में कभी पानी नहीं आता था वहां भी अब जीवन नरक जैसा हो गया है ।

अखबार में भी मैंने इस चीज़ को दिया था और अधिकारियों को मैंने निमंत्रण भी दिया था कि वे आ कर इसका अध्ययन करें कि तट-बंधों के निर्माण के बाद कितने पानी का बहाव रुक गया है और कितने पानी के बहने का रास्ता रखा गया है और किस तरह से सैकड़ों गांवों का उद्धार किया जा सकता है । अगर उनका उद्धार नहीं किया गया तो मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि न केवल अरबों रुपया पानी में चला गया है और चला जाता रहेगा बल्कि लाखों भारतीय नागरिकों का जीवन नरकमय बन गया है और बनता रहेगा । मुझे आशा है कि डाक्टर राव अवश्य इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : जो बातें अभी चौधरी लहरी सिंह जी और राव गजराज सिंह जी कह चुके हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । एक बात का मैं निराकरण करना चाहता हूं । हमारे दिल्ली के भाई श्री नवल प्रभाकर जी ने कहा है कि पंजाब वालों ने उनको डुबाया है पंजाब वालों ने दिल्ली वालों को डुबाया है ।

एक माननीय सदस्य : वह चले गये हैं ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : चले गये हैं तो क्या हुआ, चले जायें । मैं उनको कहना चाहता हूं कि पंजाब उनको डुबाता नहीं है । जो स्वाभाविक पानी आता था झज्जर की झील का नजफगढ़ की झील में वह पानी पहले वह निकलता था, जमुना में जाता था । दिल्ली वालों ने, यहां के अखबार वालों ने चिल्लाना शुरू किया और उसका नतीजा जो कुछ हुआ वह आपके सामने है । यहां पर कालोनीज़ बसा दी गई हैं जहां पानी बहता था वहां बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर दी गई हैं और पानी के बहाव को बन्द कर दिया गया । जब यह चिल्लाते हैं कि दिल्ली बह गई इस में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब का कोई कसूर नहीं है । ढांसा बांध जो आपने बनाया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह न केवल गैर कानूनी है बल्कि इसको बना करके आपने बड़ा भारी जुल्म किया है । माननीय राव साहब की शुद्ध भावना पर मुझे कोई आक्षेप नहीं करना है । लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि अगली बार भगवान न करे बाढ़ आये और अगर आ जाये तो आप यह प्रबंध करें कि जो ढांसा का बांध है, इसको तोड़ दिया जाए । अगर इसको आपने नहीं तोड़ा तो मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम इसको जबरदस्ती तोड़ देंगे फिर चाहे इसका नतीजा कुछ भी निकले ।

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

आपके इंजीनियर्ज की हालत मैं आपको बताता हूं । बहादुरगढ़ के पास दो गांव हैं खडोली और कोलासी जो पानी में डूबे हुए हैं । इनका तीन हजार बीघे का रकबा पानी में डबा हुआ है । वहां के इंजीनियर्ज ने नीचे से साइफन लगा करके यह कहा कि इनको और डुबो दो ।

श्री लहरी सिंह : ठीक है, ठीक कहा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मेरा नम्बर है बोलने का, आप न बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने दफ्तर को कह दूगा कि दो चौधरियों को इकट्ठे न बिठाया जाए ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : यह बात मैंने बहादुरगढ़ के पास के दो गांवों की आपको बतलाई है । इसका नतीजा यह है कि महिलायें तथा हमारी बहनें जब जंगलों में भी जाती हैं तो कढ़ा में बैठ कर उनको जाना पड़ता है । आप चाहें तो इसको मालूम कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सन्यासी नहीं हूं, साधु नहीं हूं, महात्मा नहीं हूं । मुझे सब से पहले अपने इलाके का फिक्र है, मुझे सब से पहले अपने इलाके का दुख महसूस होता है । जब तक अपनी दाढ़ी को रंग न लग ले, दूसरों की तरफ नहीं जाया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके की रक्षा का उचित प्रबन्ध हो और उसके लिए पूरी कोशिश हो । ढांसा बांध के जो द्वार हैं इनको ज्यादा खुलवाइये, इस बांध को तुड़वा दीजिये जिससे पानी बह कर आगे जा सके, वहीं पानी खड़ा न रहे । सुरंगें लगा कर के आगे जो स्कीम बनेगी, वह तो बनेगी और जब वह बनेगी तब उसको देख भी लिया जाएगा फिल्हाल जो पानी खड़ा हुआ है, खेती जो नष्ट हो गई है, उसका प्रबन्ध आप करें । अगले खेती इस तरह से नहीं बोई जा सकेगी । इस वास्ते इस पानी को निकालने का आप सब से पहले प्रबन्ध करें । अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो गांव डूब रहे हैं, उन गांवों के लोग अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसको जुर्म करार नहीं दिया जा सकता है । हर एक को सैल्फ-डिफेंस का पूरा अधिकार प्राप्त है । हर एक को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी रक्षा करे, अपना बचाव करे, फिर चाहे उसके नतीजे कुछ भी निकलें ।

मैं अन्त में आप से इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारे इलाके को बचायें ।

Shri Chandrabhan Singh (Bilaspur): The discussion which has been going on has been very amusing. When you want to analyse the causes, you have to remember a few basic facts. The first is the annual average rainfall: the second is the process of surface flow; the third is the process of percolation and absorption, and the fourth is the surface evaporation.

As regards annual average rainfall, statise show that this has not increased in the recent past.

The second point is that the process of surface flow of all our river valleys, is the result of thousands of years of work of nature, ultimately deciding the direction the rivers will go and fall and meet the sea. I think in our intense desire to construct national highways connecting various towns and cities all over the country, care has not been taken of storm water drains. Go along any national highway and you will find thousands of acres of land under water due to the roads which act as an embankment preventing the natural flow of water. This you see in the north, south, east and west. Railway tracks crisscross the country thousands of miles blocking the natural flow of water and creating lakes, ponds, puddles with stagnating water all along.

The big canals arising from big dams, some of them the tallest in the world some the longest in-length, others covering the biggest area against meander along the countryside with utter disregard to the natural flow of water.

The third factor, the percolation and absorption, has also been materially affected. The ground water level and underground water table has been rising at an alarming rate and the foundations of big buildings in Amritsar, Delhi and other places have been endangered. The capacity for percolation and absorption has been materially affected and this has added to the volume of surface flow.

Surface evaporation has also been affected due to humidity and moist conditions beyond all limit.

The engineers who planned the roads, the railway lines and canals have made blunders with the sole aim of effecting economy by not building enough bridges, culverts, submersible roads, overbridges and causeways and have been definitely unmindful of the natural drainage.

Shri Kashi Ram Gupta: On a point of order. Is the hon. Member reading his speech?

Shri Chandrabhan Singh: I am reading from my notes.

Mr. Speaker: I did not notice it.

Shri Chandrabhan Singh: Go to any large city in the country, Delhi, Kanpur, Lucknow, Patna, Calcutta, Cuttack, Ahmedabad, Poona or Surat and you will have ample evidence of the truth of my assertion. The tragedy is that to get more lands for *lebensraum*, living space, all the lower level areas have been colonised and thus you see the prospect of colonies remaining water bound. The pools of water and quagmire breeding mosquitoes and germs of enteric, diarrhoea, dysentery, cholera, hepatitis and other water-borne diseases become danger spots of death and destruction.

We hear of so many commissions and inquiries and every year the story is repeated *ad nauseum* with increasing impunity and complete disregard for public good, safety and amenity. It is very definitely a sad affair for which the public, the local authorities and finally the Government are fully responsible. I completely fail to understand why this state of affairs has been allowed to go on.

If you come to the villages, the story is worse than ever. There is no publicity for the villagers and the villages which remain waterlogged and water-bound for full four months in the monsoon. The villagers walk in knee-deep water daily along their lanes for all their morning easing and other amenities and they think that it is their lot to remain like that. They say:

भगवान ने हमारे भाग्य में यही लिखा है।

I recently went to a few villages in my constituency in Bilaspur district. I could not go even on horse back and had to walk with knee-deep and ankle-deep water before I could reach there. Why this should be so after 17 years of independence baffles me. I am hundred per cent certain that the Planning Minister, the members of the Planning Commission and officers of the department responsible are arm-chair theoreticians and white-collar administrators busy in air-conditioned offices and houses, travelling by planes or in air-conditioned compartments with very poor knowledge of Indian conditions. But they are experts in American, Russian and Japanese methods. I appeal to the planners to completely change their outlook, and if they cannot make room for others.

With Dr. K. L. Rao, an acknowledged expert in this sphere, I do not know about the country, but I am expecting a great deal from him. He must remove all obstacles to the natural flow of water. He must give

[Shri Chandrabhan Singh]

enough scope for easy discharge by creating fresh bridges, culverts and channels all along the railways, highways and canals which must be lined with pucca cement paving. The present tendency to leave potholes all along these channels must be stopped and along with the new constructions, special efforts must be made for easy flow of water so that there is no collection anywhere. I know this is a tremendous task, and may take 10 to 15 years to complete, but it must be completed.

Mr. Speaker: How many pages more?

Shri Chandrabhan Singh: I would appeal that every village must be connected with a good, pucca road, ultimately leading to a modern macadamised highway at a distance of three miles at the most. Let there be a road building scheme planned for seven years.

18.00 hrs.

The other day, while hearing the Members discussing the water pollution in Delhi, I was literally shocked to see Members indulging in invectives and emotional exhibitions by gesture and articulate language and blaming the Health Minister for everything. That was most unfair.

May I say that the remedy needs the concerted effort of all sections of the community, inside the House and outside, and I am sure it can be done.

May I appeal to you Mr. Speaker, and through you to the press that they must debate some space for villagers in their papers and to all other Members that some areas must be improved? I will appeal to the Prime Minister to have a special cell, a "village cell" where Finance, P.W.D., Food and Agriculture, Education, Health and Community Development will be represented. Let this be a high-powered body, and let their decision be final. What the Members of Parliament can do is to adopt five villages, one in each Vidhan Sabha constituency in collaboration with their colleagues in the State Assembly, and develop them as model villages. The first priority should be given to the development of lanes, roads, waterways, with an eye on drainage and flood prevention.

Thank you.

Mr. Speaker: Rather, I should thank him.

Some Hon. Members rose—

Mr. Speaker: I will continue listening to the speech so long as Members are prepared to make them.

श्री ग्र० प्र० शर्मा (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण न दे कर कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि खास मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। गंगा नदी में जो उस का उत्तरी किनारा है, गाजीपुर से आरा तक, उस में केन्द्रीय सरकार की तरफ से रेलवे के साथ मिल कर एक पक्का एम्बैंकमेंट बनाया गया है। नतीजा यह है कि जो नदी का दक्षिणी किनारा है वह सारा भर जाता है। उत्तरी किनारे में एम्बैंकमेंट बनने की वजह से दक्षिणी किनारे को बाढ़ धो देती है। और जो उस किनारे पर गांव हैं वह बाढ़ में डूब जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो दक्षिणी किनारे पर उसी तरीके से पक्का बांध बने, या फिर जो पानी का निकास है उसे चैनेल बना कर उस इलाके की सिंचाई के काम में लगाया जाये जिस से कि वहां पर बाढ़ कम हो। अगर दक्षिणी किनारे पर भी एम्बैंकमेंट बना दिया जायेगा तो नदी गहरी भी काफी हो जायेगी और उस में नाव आदि और स्टीमरों के चलने से एक जगह से दूसरी जगह माल लाने ले जाने में सुविधा होगी। मैं सिर्फ यह छोटा सा सुझाव देना चाहता

था और मुझे आशा है कि जो हमारे मंत्री डा० के० एल० राव हैं, जिन से मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं वे इधर ध्यान देंगे और जिस तरह से वे अपने आप जा कर और जगहों का निरीक्षण करते हैं उसी तरह से यह जो क्षेत्र है उस का निरीक्षण करेंगे और इस के लिये कुछ इन्तजाम करेंगे।

श्री इक़बाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हम फ्लड के सिलसिले में यहां बातें कर रहे हैं। उस में बहुत सा जोश भी आया, कुछ सवाल भी पैदा हुए, इंटरस्टेट मामले और दूसरे मामले में, लेकिन सब से बड़ा मसला यह है कि हर साल फ्लड का मसला क्यों बुरे से ज्यादा बुरा होता जाता है। इसलिये कि इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली टेक अप नहीं किया। फ्लड के सिलसिले में तीसरी पांच साला योजना में 90 करोड़ रुपया रक्खा गया है, और अगर मैं अलहदा अलहदा स्टेट्स की बात कहूं तो आप सुन कर हैरान होंगे कि मुझ से पहले जो भाई बोले उन के स्टेट में फ्लड के सिलसिले में 3 करोड़ रुपये के लिये कहा गया और प्लैनिंग कमिशन, ने फ्लड के लिये वह तीन करोड़ रुपये मंजूर किये। पता नहीं है कि वह फ्लड कंट्रोल मेजर्स और एन्टी वाटरलागिंग मेजर्स कितने ले सकेंगे। आखिर रिसोर्सेज की बात है। जब तक इस ढंग से काम चलता रहेगा तब तक मसला हल होने वाला नहीं है। इस में तो और लोगों की तकलीफें बढ़ेंगी।

सब से पहले तो मैं यह कहूंगा कि मिनिस्टर महोदय, प्लैनिंग कमिशन के पास जायें और आज जो हालत है उस के सिलसिले में उन से बात करें। जिस स्टेट का जितना मसला है उस के मुताबिक उन को पैसा दिया जायें ताकि मसले के खत्म होने के आसार नजर आये। वर्ना हर साल लम्बी बहस होगी और लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। यह लोगों की एकानमिक कंडिशन का मसला है और हर एक आदमी जिस इलाके से वह आता है उस के मुताबिक बात करता है। आखिर हम एक डिमाक्रेटिक सिस्टम को मानने वाले हैं और हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बात करते हैं। मैं इस सिलसिले में इतना ही कहना चाहता हूं कि पैसा बढ़ाना चाहिये।

इसके बाद मैं पंजाब की तरफ आता हूं। मेरे सामने बहुत से आदाद व शुमार हैं। सन् 1955 से लेकर 1960 तक पंजाब के लिए मंजूर हुए 15 करोड़ रुपये तब किसी साल 30 करोड़ रुपये, किसी साल 12 करोड़ रुपये किसानों के घरों के लिये और उनकी जमीनों के लिये। अगर आज तक का टोटल किया जाये तो पिछले सात आठ सालों में करीब 150 करोड़ रुपये मंजूर हुए। इसके अलावा भी आपने इस सिलसिले में पंजाब को रिलीफ दिया है। एन्टी वाटरलागिंग के लिये और फलड कंट्रौल के लिये। जिस वक्त पंजाब की तकसीम हुई उस वक्त उसका वाटरलाग्ड एरिया 9 लाख एकड़ का था और आज 40 लाख एकड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना कहता हूं कि पंजाब सरकार ने हिम्मत की, कुछ मेहनत की, कुछ लोगों के जजबात थे, क्योंकि जो पंजाब की सब से बड़ी प्राब्लेम है वह यह है कि जो खेती करने वाले हैं, जो खेती की वजह से मेहनत करते हैं, उन किसानों का सब कुछ निर्भर करता है इसी बात पर कि वहां खूब पैदा हो और उसकी आमदनी से वह अपना गुजारा कर सकें। उन्होंने पिछले तीन सालों में पहले साल 7 करोड़ रुपया लगाया, दूसरे साल 20 करोड़ रु० लगाया और इस साल 10 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। 10 करोड़ रु० की उनकी मांग और है। इसको गिन लिया जाये तो उन्होंने 47 करोड़ रुपया लगाया। सेंटर ने 11 करोड़ रुपये दिये। 27 करोड़ रु० के उनके अपने रिसोर्सेस थे। यह इसलिये किया गया कि पंजाब के लोगों के मसले की तरफ से कोई भी सूबे की सरकार, चाहे पहली सरकार हो चाहे आज की सरकार हो अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं डा० के० एल०राव से इतना कहना चाहता हूं

[श्री इकबाल सिंह]

कि वह उनको पैसा दिलाने की कोशिश करे ताकि उनका मसला हल हो सके, वर्ना यह मसला हल नहीं होगा । अगर पैसा नहीं होगा तो यह मसला हल नहीं हो सकता । आज जिस किस्म का पंजाब का ड्रेनेज का प्रोग्राम है, उसके लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है । आज कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब की सरकार ने डुबा दिया । एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां पर पंजाब की सरकार ने ड्रेनेज को चेनेलाइज किया है वहां पर उसने कोई डैम नहीं बनाया । इसलिये नहीं कि डैम्स बनाना सब से बड़ा गुनाह है और इससे बड़ा गुनाह हमारे यहां की सरकार नहीं कर सकती थी, बल्कि उसने सब बातों को सोचा । मैं एक लेमैन के तौर पर कह देना चाहता हूं कि तीन साल तक पंजाब और दिल्ली का झगड़ा चला । नजफगढ़ ड्रेन जो है वह 200 क्यूसेक्स का बने या साढ़े चार सौ क्यूसेक्स का बने । इससे ज्यादा कोई झगड़ा नहीं है । लेकिन इस साल नजफगढ़ ड्रेन में 15,000 क्यूसेक्स पानी आया । मैं पूछना चाहता हूं कि वह इंजीनियर किस किस्म के थे जिन्होंने यह फैसला कर दिया कि जहां पर 15,000 क्यूसेक्स का बहाव हो, वहां पर कम बहाव को मान लिया । कभी दिल्ली वाले उकसा देते हैं कि 200 क्यूसेक्स लो, कभी पंजाब वाले कहते हैं कि 450 क्यूसेक्स । फिर फैसला कर लेते हैं 450 क्यूसेक्स पर । इससे एक बात निकलती है कि इस तरह पर वह डैम बनाते हैं और 15,000 क्यूसेक्स के बहाव को रोकते हैं । इससे जिन लोगों की मिजरीज बढ़ेंगी उनका रिएक्शन क्या होगा, उनकी एकानमिक कंडिशन पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी तो कुछ सोचना चाहिए । इसको सोच कर इंटरस्टेट मसलों को हल करना चाहिये । पंजाब को भी सोचना चाहिये, बाकी की स्टेट्स को भी सोचना चाहिये । यह जो बात आप करने लगे हैं वह गलत है । इस तरह से आप किसी ड्रेनेज को चैनेलाइज नहीं कर सकते । अगर आप चैनेलाइज नहीं कर सकते हैं तो स्पेस दे लगाते । अगर आप गेट लगाते हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बहाव आयेगा और इससे ज्यादा बरसात नहीं होगी । इसके अलावा जो पंजाब का इलाका दिल्ली के नजदीक है उसकी ऐब्जोर्वेंट कैपेसिटी कहां गई कि पानी का बहाव ऊपर आ गया और उसको रिटेन नहीं किया जा सकता ।

दूसरा जो सब से बड़ा मसला डैम्स के सिलसिले में है वह उनको चैनेलाइज करने का है । उसके साथ बड़ा मसला कि बिजली दें ताकि ट्यूब वेल लगें जिसमें कि पानी की जो सतह है वह नीचे जा सके और जमीन की ऐवजार्वेंट कैपैसिटी बढ़े और उसके साथ लोगों को फायदा हो सके ।

आखिर में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ आता हूं । मैं डा० राव से कहना चाहता हूं कि वहां के लोग झगड़ा करते हैं कि बावजूद इसके वहां पर हमने 50,000 क्यूसेक्स का ड्रेनेज बनाया है, इस बात का मसला है कि उसको डालना है सतलुज में, राजस्थान कैनाल में । लेकिन इस मसले के रहते हुए भी वहां कुछ नहीं हो सकता जब तक आप बिजली न दें । पंजाब और बाकी स्टेट्स के जो मसले हैं उन पर आपको सिंपैथिकली गौर करना चाहिये । यह कोई स्टेट का मसला नहीं है, यह ह्यूमन फीलिंग का मसला है और इसको ह्यूमन फीलिंग के ढंग से ही सोचना चाहिये । मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं । आज लोगों के रिएक्शन इंजीनियस के खिलाफ हैं । अगर ये जज़बात बढ़ते गये तो उनके खराब रिपरकशन होंगे । आज लोग कहते हैं कि हमारे गांव तबाह हो गये लेकिन हमारी खबर लेने वाला कोई नहीं है । मैं यही कहता हूं कि इस तरफ तवज्जह देना जरूरी है ।

श्री श्रीनारायण दास : बाढ़ प्राकृतिक प्रकोप है लेकिन इससे जो जान माल

की क्षति होती है वह मनुष्य कृत है । इसके सम्बन्ध में मैं पहले भी सदन में बोल चुका हूं कि इसके लिए रेलवे, रोड और नहर विभाग जिम्मेवार हैं । बाढ़ का पानी पहले भी आता था लेकिन वह अपने रास्ते से निकल जाता था । लेकिन जब से रेलवे लाइन का, सड़कों का तथा नहरों का निर्माण हुआ है, पानी का बहाव रुक गया है । इससे नुकसान होता है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए जो देखे कि कहां कहां रेलवे लाइन के निर्माण में पानी के लिए कम स्थान दिया गया है, कहां कहां सड़कों के निर्माण में पानी को निकासी के लिये कम स्थान दिया गया है । अगर इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाएगा तो बाढ़ का पानी निकल जाएगा और फसल बरबाद न होगी । सड़क बनाने में खरचे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है यह नहीं देखा जाता कि अगर पुल छोटे बनेंगे तो पानी रुकेगा । इसलिए बाढ़ से नुकसान होता है ।

हमारे माननीय मन्त्री जी मेरे क्षेत्र में गए थे । वहां जिन स्थानों पर बाढ़ के समय दस दस पन्द्रह पन्द्रह फीट पानी था वहां पर दो महीने के बाद चिल्लू भर पानी नहीं रहा । इस इलाके में हर साल बाढ़ आती है और फसल बरबाद हो जाती है । मेरा सुझाव है कि इस इलाके के लिए किसी अरली क्राप की योजना बनायी जाए जो कि जेठ बैसाख के महीने में उगा ली जाए ताकि बाढ़ से लोगों को नुकसान न हो । इन महीनों में वहां कुछ सिंचाई का प्रबन्ध कर दिया जाए तो उनकी फसल हो सकती है और व बाढ़ के नुकसान से बच सकते हैं ।

बिहार में इस साल दो बार बाढ़ आयी । एक बार बाढ़ आयी तो सारी फसल बरबाद हो गयी । बाद में लोगों ने फिर मेहनत करके जहां तहां से लाकर धान के पौधे लगाए । लेकिन फिर दूसरी बार बाढ़ आ गयी और फिर सारी फसल खराब हो गयी । इससे वहां बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है, वहां के लोगों का क्या भविष्य होगा, मवेशियों के चारे का क्या इन्तिजाम होगा, आदमियों के खाने का क्या इन्तिजाम होगा । यह भारी सवाल है । इसलिए मेरा सुझाव है कि बिहार में इस साल मालगुजारी की वसूली न की जाए, तकावी की वसूली रोकी जाए और वहां के लोगों के लिए खाने पीने का इन्तिजाम किया जाए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । इस समय में अनाज का संकट हो गया था इस इलाके में । बाढ़ के समय बहुत थोड़ी सहायता दी जा सकी क्योंकि चारों ओर पानी भरा था । लोगों को अनाज नहीं मिलता था । सरकारी दुकानों पर भी गल्ले का अच्छा इन्तिजाम नहीं किया गया । इससे बहुत क्षति हुई है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस इलाके में अधिक सरकारी अनाज भेजने का इन्तिजाम करें । खास कर उत्तरी बिहार के चम्पारन, सहरसा, मुंगेर आदि जिलों में हर साल बाढ़ आती है । मैं समझता हूं कि उसके लिए तटबन्ध का इन्तिजाम किया गया है । लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, इन से फायदा भी होता और नुकसान भी हो सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तटबन्ध की नीति पर विचार करने के लिए हाई लेविल पर विचार किया जाना चाहिए । मेरा विचार है कि पौनी का नेचुरल फ्लो रखा जाए ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तक जितने माननीय सदस्यों को सुना, किसी ने एक गांव की बात कही किसी ने दूसरे गांव की बात कही । असल में यह एक नेशनल प्राबलम है और सरकार को इसे एक नेशनल प्राबलम की तरह लेना चाहिए । इस पर सारे देश के लिए 70 या 80 करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए । इस मामले में एक दूसरे को दोष देना गलत बात है । यह तो सेंटर की जिम्मेवारी है ।

फूड, फारेस्ट और फ्लड ये तीनों मामले एक दूसरे से मिले हुए हैं । तीन तरह का एरिया है, पहाड़ी, मैदानी और डेल्टाई । अगर

[श्री शिव नारायण]

आप पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे बांध बना दें तो वहां पानी रुक जाए । पानी को रोकना चाहिए । जंगल साफ़ कर दिए गए हैं इसलिए मैदान में सीधा पानी चला आता है ।

पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज था तो इतनी बाढ़ें नहीं आती थीं, लेकिन आज जंगल कट गए हैं इसलिए पानी नहीं रुकता । पंडित जी ने सन् 35 में गोरखपुर में कहा था कि कैसे निकम्मे इंजीनियर हैं जो इसकी रोकथाम नहीं कर सकते । मैं आज अपने इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं कि यह क्या गड़बड़ है, उसका इन्तिजाम क्यों नहीं कर पाते । मेरी दरख्वास्त है कि मिनिस्टर साहब से वे इस मामले को खुद अपने हाथों में लें और 70 या 80 करोड़ रुपए की एक स्कीम सारे देश के लिए बनाएं । मैंने सन् 1953 में उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम को हर साल घाघरा नदी से 80 करोड़ की हानि होती है । अगर 80 करोड़ रुपया खर्च करके इसको कण्ट्रोल कर लिया जाए तो इस इलाके की दशा बहुत सुधर सकती है । मैंने इस बारे में पंडित जी से सन् 1956 में लखनऊ में कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक बांध बना रहे हैं । मेरा सुझाव है कि इस मामले को केन्द्रीय गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ।

जहां तक गांवों के पास बांध बनाने का सवाल है, मेरा कहना है कि इससे एक गांव की रक्षा तो हो जाती है पर दूसरे गांव को नुकसान होने लगता है और हमारे यहां इस कारण गोली तक चली और एक प्रोफेसर जो एस०डी०एम० हो कर आया था उसकी जान ही बच गयी ।

हमारे के०एल० राव साहब चीन हो कर आए हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह नेशनल प्राबलम है । यह आसान काम नहीं है । इस पर अमल कीजिए और इस काम को अपने हाथ में लीजिए, इसको किसी स्टेट पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसका खुद कीजिए । पानी का फ्री चैनल होने का इंतजाम किया जाना चाहिए । यह तो हम ले मैन भी जानते हैं । एक्सपर्ट लोगों को तो इसे और भी समझना चाहिए ।

मान्यवर मैं जिस जिले से आता हूं उसमें सात सात नदियां हैं । उत्तर बस्ती में बरसात में समुद्र सा बन जाता है । मैंने राव साहब से कहा कि नेपाल सरकार से बात करके अगर डैम बना दें । अगर एक साल भी हमारे यहां बाढ़ रुक जाए तो हम इतना चावल पैदा कर सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान को खिला दें । घाघरा के कण्ट्रोल हो जाने से उसके किनारे इतना चावल, मक्का और दूसरा अनाज हो सकता है कि चार साल तक खाने को काफी हो जाए । हमारा काम बतला देने का है, आगे सरकार का काम है कि वह देखे या न देखे । हमने सही बात बतला दी । मैं फिर कहता हूं कि सरकार 70–80 करोड़ का मुंह न देखे । एक बार हिम्मत करके इस फोड़े का आपरेशन कर दे ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत गम्भीर है और इस पर सरकार को बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए । यह देश के लिए बहुत गम्भीर समस्या है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय इस बाढ़ के सम्बन्ध में काफी सदस्यों ने भाषण दिए और अच्छे अच्छे विचार आपके सामने रखे । मैं भी अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं ।

बाढ़ की समस्या सारे देश की समस्या है और हमेशा की समस्या है, हर साल बाढ़

आती है और हर बार हम यहां चर्चा करते हैं। पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर यह बाढ़ आती क्यों है। पानी जमा होता क्यों है। इसके लिए कुछ विशेषज्ञ इंजिनियर बुला कर इस पर विचार करना चाहिए और ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि गांवों के निकट पानी जमा न हो। पानी निकलने का ठीक रास्ता होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां मध्य प्रदेश में बहुत कम बाढ़ आती है। सब जगह पानी बरसता है लेकिन बाढ़ नहीं आती। इसका मूल कारण यह है कि मध्य प्रदेश में हर गांव के पास एक बड़ा तालाब है और उसके पास कुछ नदियां और नाले होते हैं। तो जो पानी आता है वह तालाब में जमा हो जाता है और कुछ नालों और नदियों में बह जाता है। मैं पंजाब में घूमा हूं, लेकिन मैंने वहां तालाब नहीं देखे तालाब हों तो उनमें पानी जमा हो जाए और उसको बारह महीने देहात के लोग अपने निजी उपयोग में ला सकते हैं और उससे छोटी सिंचाई भी हो सकती है। इससे उपज भी बढ़ सकती है। तो यह पानी 12 महीने तक चल सकता है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के तालाब बड़ी तादाद में बनाएं जाएं जिनमें चारों तरफ का पानी एकत्र हो जाए ताकि उससे छोटी सिंचाई योजनाएं चल सकें।

मैं बड़ी योजनाओं के विरुद्ध हूं। लेकिन शासन आज बड़ी योजना के पीछे पड़ा है। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी नहरों से पानी दिया जा रहा है। अगर इन नहरों का कोई भाग टूट जाता है तो उससे आस पास के इलाके के गांव जलमग्न हो जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि सिंचाई की छोटी छोटी अनेकों योजनाएं बनाई जायं और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उचित तथा सस्ते रेट पर दिया जाये। इस के अलावा बाढ़ अथवा कटाव के कारण जिन लोगों का नुकसान होता है, जिनको काफ़ी पीड़ा होती है, उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को ज़रूरी शिक्षण देना चाहिए ताकि संकट के समय वे असहाय बन कर खड़े न हो जायं और केवल सरकारी सहायता के लिए ही मुंह न ताका करें क्योंकि एक तो वह सहायता मिलती ही बहुत कम है और अगर मिलती भी है तो देर में मिलती है। ऐसे समय में वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें, वे अपने मवेशी, सामान और जान किस तरह से बचा कर निकलें इस की शासन द्वारा कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

इस के अलावा मेरा इस बात का अनुभव है कि हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आती तो उस क्षेत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बाढ़ आने पर तुरन्त लोग अपने गांव छोड़ कर, अपने मकान आदि खाली करके अपना पूरा सामान, मवेशी आदि लेकर कहीं ऊंची जगहों पर चले जायें।

जहां तक गांवों को ऊंचा करने का सवाल है यह एक बड़ी लम्बी योजना है और इस में काफी पैसा लगेगा लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब गांव के अन्दर पानी आये तो वह देहात में न चला जाय और वह पानी किसी दरिया, तालाब आदि में जाकर मिल जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस अपार क्षति का जिक्र किया है जोकि इन बाढ़ों से हमेशा हमारे देशवासियों को होती रही है। इस सम्बंध में मुझे चाणक्य का यह कथन याद आ जाता है कि जिस नगर में ज्यादा चोरियां हों तो उस होने वाली धन हानि का हर्जाना उस नगर की पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों को दिलवाया जाना चाहिए। वहां की पुलिस को उस का हर्जाना भरना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वही चाणक्य वाला सिद्धान्त यहां बाढ़ के सम्बन्ध में भी लागू किया जाये अर्थात् बाढ़ के कारण, कटाव के कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है, शासन द्वारा उसकी भरपाई की जाय। जितना उनका रुपयों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

और मवेशियों का नुकसान हुआ है उस सारे नुकसान को मंत्री महोदय को अपनी ओर से भरना चाहिए ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक उनको पैसे की सहायता देने का सवाल है पैसे की मदद दी जाय लेकिन खाली पैसा देने से ही उन की समस्या हल नहीं होने वाली है । देखना यह चाहिए कि उनका किस चीज का नुकसान हुआ है ? अगर जमीन का नुकसान हुआ तो उन्हें आलटरनेट लैंड देना चाहिए, फसल का नुकसान यदि उनका हुआ है तो उन्हें अनाज मुहैया किया जाय । कृषि का उत्पादन करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में बीज दिये जायं । जिनके मवेशी मर गये हैं उन्हें सरकार मवेशी दिलाये । जिनके मकान बाढ़ में गिर गये हैं सरकार उनके नये मकान बनवा कर खड़े करे । मैं और अधिक न कहते हुए सिर्फ यही चाहूंगा कि मैं ने जो चंद एक सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, डा० के० एल० राव ने सदन के सामने जो स्टेटमेंट रखा है उस को पढ़ कर यह मालूम होता है कि पूरी हालत से वह भी शायद वाकिफ़ नहीं हैं । यह उन का दोष नहीं है क्योंकि हमारे सूबे की सरकार अक्सर रिपोर्ट भेजा भी करती है लेकिन मैंने इस सदन में बारबार यह सवाल किया है और दूसरे माननीय मित्रों ने भी किया है कि आखिर मास्टर प्लान का क्या हुआ ? उत्तर प्रदेश के बारे में कहा यह जाता था और इस सदन में यह भी बतलाया गया कि उत्तर प्रदेश का मास्टर प्लान फलड्स कंट्रोल के लिए एक मास्टर प्लान बनाने जा रहा है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उस प्लान का क्या हुआ और उस मास्टर का क्या हुआ ? दोनों ही अलग हो गये, कुछ बात समझ में नहीं आती है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वी जिलों में जहां पर सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है और सारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, विशेष कर पूर्वी जिलों की हालत को आप देखें तो आपको पता चल जायेगा कि स्थिति कितनी विषम हो चली है । यह उनका कल्याण कब होगा और किस प्रकार सरकार के द्वारा होगा, इसका कुछ पता नहीं है । इस के बारे में शायद वहां के लोग सोच ही नहीं सकते हैं । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है, उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लिये भी आखिर क्या हुआ ? क्या वह रुपए की वजह से रुक गया है ?

श्री इकबाल सिंह : उत्तर प्रदेश को ७० करोड़ मिले उस में से 2 करोड़ लखनऊ पर लगा दिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं । हमारे यहां झगड़ा हो जाया करता है जिसका कि फायदा आप उठाना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि हमारे यहां झगड़ा हो रहा है और उस का फायदा आप लोग उठाना चाहते हैं....

श्री इकबाल सिंह : मैं तो एनफोरसेशन दे रहा हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर इसे बिलकुल न छोड़ा जाये क्योंकि हमारे यहां मुसीबत यह है कि यहां पर जिस तरह से सैलाब की चर्चा हो रही है, उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सैलाब आ जाया करते हैं । उसमें हम लोगों की अक्सर डूबने की हालत हो जाती है लेकिन चूंकि हमें तैरना आता है इसलिए तैर कर निकल जाते हैं । राव साहब खुद भी उत्तर-प्रदेश गये थे । उन्होंने वहां का दौरा किया

था। उन्होंने वहां की हालत स्वयं देखी और बाढ़ पीड़ित गांवों का निरीक्षण किया। श्री सिंहासन सिंह की यह बात बिलकुल सही है कि जहां पर गांवों को उठाने का सवाल था, रेजिंग आफ़ दी विलेजेज़ का सवाल था, यह देखने की जरूरत है कि कहां उठा, किस का गांव उठा या किस का मकान उठा? इस सम्बन्ध में मैं तीन, चार सुझाव उन के सामने देना चाहता हूं। एक तो यह है कि मास्टर प्लान जिस तरीक़ से लागू करने की कोशिश है वह फौरन लागू किया जाय। दूसरी चीज यह है कि जब देश में रेलवे ऐक्सीडैंट्स बढ़ने लगे तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और इस सदन में यह कहा गया कि कम से कम उन ऐक्सीडैंट्स को किसी तरीक़े से भी ऐवाएड किया जाय। किसी तरह से यह ऐक्सीडैंट्स कम किये जायें। ताकि हियुमन फेल्योर से न हों दूसरी किसी वजह से हो जाय तो हो जाय। उस को देखने के लिए आप ने कुंजरू कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई और उस की रिपोर्ट को हम ने देखा कि आखिरकार काफ़ी अच्छे सुझाव हमारे पास आये जिससे ऐक्सीडैंट्स एकदम दूर तो नहीं हुए लेकिन कम से कम मुख्य कारण जो उनके थे वे हमें मालूम हुए। मैं चाहता हूं कि उसी आधार पर इस बाढ़ की समस्या को भी विचारा जाय। मंत्री महोदय खुद बड़े योग्य व्यक्ति हैं। जिस विभाग के वे मंत्री हैं उसका उन्हें स्वयं बहुत अच्छा अनुभव व ज्ञान प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि जैसे खोसला कमेटी बनी थी वह एक वैसा ही हाई पावर कमिशन या कमेटी बनायें जैसे कि रेलवे ऐक्सीडैंट्स को दूर करने के लिए बनी थी। ऐक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाय जिसमें ऐक्सपर्टस हों, और संसद् सदस्य आदि हों। जब वह ऐक्सपर्ट कमेटी जिसके कि सदस्यों को इस बारे में काफी ज्ञान है जब वह इस बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे तब मैं समझता हूं कि हमें यह सब मालूम होगा कि आखिर यह बाढ़ की समस्या है क्या और इसकी लैंथ और ब्रैड्थ क्या है? तब पता चलेगा कि यह कसी अहम और संगीन समस्या है?

रेलवे के कल्वर्ट्स के बारे में मुझे यह कहा है कि दूर न जाकर आप अभी यहां से मेरठ जाने का कष्ट करें तो बारिश के समय में कुछ जगहों पर रास्ते में चलना मुश्किल है कोई गाड़ी वहां पर चल नहीं सकती है। रेलवे लाईन्स तो हम लोगों ने 37000 मील बनाई लेकिन यह नहीं सोचा था कि पुलियों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि इन पुलियों के बनाने के कारण कुछ ज्यादा पैसा खर्च हो जाता लेकिन उस ज्यादा पैसे खर्च होने के डर में आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आज कल्वर्ट्स के न बनने से हुआ यह है कि हमारी ट्रेन सर्विस सस्पैंड हो गयी है।

यहां दिल्ली के बारे में मैं बतलाऊं कि हालां कि कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है तो भी हम ने अभी उस दिन जब दिल्ली शहर में बारिश हो गई तो देखा कि डिप्लोमैटिक एनक्लेव की बस्ती जोकि नयी ही बनी है वहां का ड्रैनेज सिस्टम इतना डिफैक्टिव है कि डिप्लोमेट्स की डिप्लोमेसी धरी रह गयी और वह घरों में ही बैठे रह गये वह बाहर नहीं निकल सके। यह हालत तो दिल्ली शहर की है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे किसान भाइयों को बाढ़ से कितना नुकसान होता होगा और कितनी उनमें तबाही होती होगी? जरूरत इस बात की है कि बाढ़ के संकट के समय उनको तकावी दी जाय और कोई सूद उनसे न लिया जाय। बगैर सूद के उनको यह तकावी दी जाय न कि यह सवा 6 फीसदी सूद उन से ले लिया जाय। मालगुजारी उनकी बिलकुल माफ कर दी जाय और उन्हें कपड़ा, बीज, अन्न आदि मुहैय्या किया जाय। एक तरफ तो वे बाढ़ से पीड़ित होते हैं और दूसरी तरफ़ उनके सामने समस्या रहती है कि अपनी आवश्यकता की चीजें किस तरीक़े से खरीदें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस कमीशन मुकर्रर करने की डिमांड को मंजूर करेंगे ताकि एक परमानेंट बेसिस पर वह इस समस्या पर काबू पाने का उपाय सोच सकें। इस कमीशन की मांग को स्वीकार करने में उनकी असफलता नहीं होगी बल्कि उनका

[श्री स० म० बनर्जी]

बड़प्पन और भी ज्यादा होगा । बस मेरा यही निवेदन है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री को केवल एक सुझाव इस बाढ़ के सम्बन्ध में देना चाहता हूं । उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बार कहा था कि वैसे तो बड़ी नदियों से बाढ़ प्रायः आती रहती है लेकिन छोटी नदियां भी इतना अधिक नुकसान कर सकती हैं यह इस बाढ़ से ही अनुभव हुआ लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि शायद उनके कानों तक यह बात नहीं पहुंची कि छोटी नदियां भी पिछले वर्षों में नुकसान करती रही हैं । पिछले वर्षों में बाढ़ के जो परिणाम रहे हैं वह इस का परिचय हम को देते हैं । बड़ी नदियों के सम्बन्ध में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की बाढ़ से जहां जहां हानि होती है उस की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह हानियां दो प्रकार की हैं । एक तो यह कि वर्षा ऋतु में जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो उसके ऊंचे किनारों पर बसे हुए गांव से कट कट कर उनकी भूमियां समाप्त होती हैं और गांव के गांव उजड़ जाते हैं । उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र है । बिजनौर जिले में लालवाली के पास जब गंगा आगे को बढ़ती है तो करीब ६-७ गांव गंगा की इस तरह कटान से उजड़ चुके हैं और गंगा के प्रवाह में कट गये और धरतियां सहारनपुर जिले में चली गईं । उन उजड़े हुए लोगों को दूसरे स्थान पर अभी तक धरती नहीं मिल पाई है । इस तरीक़े से वह प्रश्न फिर सामने खड़ा है । यह जो कटाव हुआ है यह भी बाढ़ का ही बहुत बड़ा परिणाम है । इसलिए इस कटाव से भी बचने का कोई उपाय करना चाहिए ।

गंगा नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में मैं एक बात और यहां कहना चाहता हूं । गढ़मुक्तेश्वर से लेकर अनूपशहर और उससे आगे राजघाट तक जब गंगा नदी में से नहर निकली है, धीरे धीरे गंगा नदी में रेत का जमाव इतना अधिक बढ़ रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर और अनूपशहर के बीच में सावन भादों का महीना जब आता है तो गंगा नदी का पानी बड़ी आसानी के साथ चारों ओर फैल जाता है । उसका परिणाम यह है कि पड़ोस की जो छोटी छोटी नदियां हैं, वह प्रवाह उन में आ कर पड़ जाता है । मुरादाबाद जिले में हसनपुर तहसील का बहुत बड़ा इलाका इस प्रकार का है, जिस की लाखों बीघे की फ़सल प्रति वर्ष गंगा की बाढ़ के हवाले हो जाती है ।

उत्तर प्रदेश के पिछले सिंचाई मंत्री, चौधरी चरण सिंह, के सामने जब मैं ने यह सुझाव उपस्थित किया, तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारों को रोकना, जिससे वह पानी इधर-उधर न फैल सके, बहुत अधिक व्यय-साध्य होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसी तरीक़े से रेत को निकाल कर नदी को गहरा कर दिया जाये, ताकि उस का पानी अपने सीमित क्षेत्र में बहे । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की वह योजना अभी तक योजना-मात्र है और उस को व्यावहारिक रूप नहीं मिला है ।

डा० के० एल० राव स्वयं इन सारी बातों के विशेषज्ञ हैं और एक कुशल इंजीनियर हैं । मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह उस क्षेत्र की ओर भी विशेष ध्यान दें, जहां न कोई सड़क है, न कोई हास्पिटल है, न कोई रेल-गाड़ी पहुंचती है और न जहां के लोगों की आवाज़ ही सरकार के कानों तक पहुंच पाती है । गंगा नदी में बाढ़ आने से प्रति वर्ष लाखों बीघे की फ़सल नष्ट हो जाती है । नरौरा से जो नहर निकलती है उसकी वजह से रेत रुकते रुकते गढ़मुक्तेश्वर तक गंगा का लेवल ऊंचा हो गया है । यदि माननीय मंत्री जी उस को गहरा करने की व्यवस्था करेंगे तो वहां के लाखों व्यक्तियों को लाभ होगा ।

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): In spite of his great anxiety, the reason why the present Minister has not succeeded in solving the problem is the fact that there is no organisation which can help him in working out his schemes. What I mean is this, that we need a special commission or special body—I made this suggestion last year too to the hon. Minister—which will exclusively and constantly pay sole attention to this problem and will try to solve it. We need a body here in the Centre as well as in the States down to the district level. We should have a separate body which would for all the twelve months in the year pay full attention to this problem and to no other. The setting up of such a body is one of the ways of solving this problem.

We have floods every year, and this body should be allotted sufficient funds to deal with this problem. It should have on it representatives from the different Ministries which are concerned with it, such as the Railway Ministry, the Ministry in in charge of Communications, the Health Ministry, Works, Housing and Supply Ministry and the Food and Agriculture Ministry. I hope that such a body will be brought into existence very soon. Then it will be much easier for the present Minister and for everybody else to be able to give relief to the people who are affected. and to prevent floods in the future.

The second reason why we need such a body is that although the Centre may be very anxious, the States are not equally anxious in regard to this matter. I shall give an example. Recently, a note has been circulated with certain figures. So far as UP is concerned, I can assure the hon. Minister that those figures are totally wrong. I have myself been visiting some of the flooded and water-logged areas of three districts of UP. In Aligarh, 15 people have died, and several hundreds of villages have been flooded and waterlogged. In Mathura, at least three tehsils have suffered immense damage. Then, there is an area about fifteen miles from Mathura on the way to Hathras town, which is like a sheet of water. There is another place in one of the tehsils in Mathura district, where there is a lake about ten miles in length, which has affected very good and fertile land of about eighteen to twenty villages. Nothing has been done in this regard simply because the local officials and the State Government have not taken adequate steps. In Etah also, conditions are more or less similar.

Therefore, if we have one organisation which will constantly pay attention to this problem, we can expect that it may be solved within a reasonable limit of time.

One word about gratuitous relief. Gratuitous relief is inadequate. I would suggest that taccavi should not be given. It is a great nuisance. When people go to get taccavi, they have to pay a portion of it to the petty officials. When the time comes for realisation of the taccavi, they have quite often to be put into lock-up because they cannot afford to pay back. The best thing is to give them as much help as possible in the shape of gratuitous relief.

I would like to emphasise here that we should have a scheme for construction of houses in rural areas. Whenever a village has been des-destroyed by floods, we should have a plan ready to build a fresh village, if we are serious about housing schemes in rural areas. This is an ideal opportunity which nature has afforded us and we should take the fullest advantage of it and put into effect schemes of housing in rural areas.

श्री बृजराज सिंह—कोटा : मैं माननीय मंत्री से सिर्फ एक मिनट के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने—और खास कर पंजाब के माननीय

[श्री बृजराज सिंह—कोटा]

सदस्यों ने—वाटरलागिंग की बड़ी शिकायत की है, क्योंकि उनके क्षेत्र में इरिगेशन को कैनाल्ज बहुत बन चुकी हैं। जिस प्रदेश और जिस जिले से मैं आता हूं, वहां पर चम्बल की कैनाल्ज बनाने की योजना है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां कोटा में कम से कम इस ओर खास ध्यान दिया जाये, ताकि जो घटना पंजाब या यू० पी० में इन कैनाल्ज की वजह से घट चुकी है, वह हमारे क्षेत्र में न घट सके। अगर शासन की ओर से अभी से प्लानिंग को ठीक कर दिया जाये, तो हमारे एरिया में बहुत कुछ बच जायेगा, वर्ना कुछ वर्षों बाद वहां भी वही हालत होगी, जो कि इस समय पंजाब और यू० पी० आदि में हो रही है।

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ के सम्बन्ध में दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

बाढ़ में जिन लोगों का नुकसान होता है—और अधिकतर काश्तकारों का नुकसान होता है—वे बाढ़ के बाद अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकते। उन को जो सबसिडी देनी है, वह तो दे दी जाये, लेकिन इसके अतिरिक्त उनको लांग-टर्म लोन भी दिये जायें, जो कि पन्द्रह बीस बरस में वापस दे सकें— जैसे कि बंडिंग और कुओं के लिए दिये जाते हैं—, ताकि बाढ़ से पहले उन लोगों की जो स्थिति थी, वे तुरन्त उस स्थिति तक पहुंच जायें और काम पर लग जायें।

बाढ़ के बारे में हम बहुत दिनों से पढ़ते हैं और सुनते हैं। आज-कल बाढ़ें बहुत आती हैं और उनसे बहुत नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि इंजीनियरिंग की दृष्टि से इस समस्या को स्टडी किया जाये। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री शास्त्री, ने कहा है, जब बाढ़ आती है, तो गांव कट जाते हैं, नुकसान होता है और मकान गिर जाते हैं। मेरा सुझाव है कि जिन गांवों में पिछले दो, तीन या दस बरस से बाढ़ आ रही है, उनके निवासियों को कहा जाये कि वे लोग वहां से उठ कर ऐसी जगह बस जायें, जहां बाढ़ से नुकसान न हो। यह प्लानिंग करने की बड़ी आवश्यकता है।

Dr. M. S Aney: Considering the extent of the damage and the wideness and vastness of the problem, I believe a separate Commission ought to be appointed by the Government of India to investigate into the whole problem as an all-India problem. That is one thing very necessary.

For the last 15 years the Planning Commission have been sitting and studying the entire problem of Indian economic uplift. Yet, the question of the damages done by the floods and the rate of relief that should be given has not received any adequate consideration, in fact no consideration at all, at the hands of the Planning Commission. It is rather a matter of surprise.

Therefore, I feel it is necessary to have a separate Commission.

I agree with the suggestion made by my hon. friend there that there should be a separate organisation also to help the Minister in charge of this problem here to give his undivided and devoted attention to the problem througout the year.

If these things are done, there is a possibility of the question being tackled in a proper spirit.

Mr. Speaker: Shri Jyotishi. There is still one more Member who has not spoken. There is no audience, all are speakers.

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन में जो भाषण हुए हैं उनको सुन कर मुझ

जैसा आदमी इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि सरकार अब तक जो कुछ करती आई है लोगों का मत है कि वह बेवकूफी ही करती आई है । यही प्रायः सभी भाषणों का मन्तव्य प्रतीत हुआ । सरकार ने सड़कों का जो निर्माण किया, वह गलत किया, रेलों का निर्माण किया, वह गलत किया । यही इम्प्रेशन मुझे मिला है । बड़े जोश खरोश के साथ, बड़ी मजबूती के साथ यहां पर भाषण हुए हैं । उनको सुन कर यही धारणा बनती है निश्चित रूप से कि शासन बड़ी बेवकूफी कर रहा है । सड़कें जो शासन ने बना रखी हैं उनके कारण बाढ़ें आती हैं, रेलें जो बना रखी हैं उनके कारण बाढ़ें आती हैं और इस तरह के जो दूसरे काम कर रखे हैं, जैसे नहरें बनाने के कारण, बाढ़ें आती हैं (इंटरप्शंज) इस तरह की बात जब कही जाती है तो मैं उससे कतई सहमत नहीं हो सकता हूं । मेरा पक्का यकीन है कि हजार कोशिश हम कर ले, ऐसे मौके आयेंगे, जब पानी छिड़ेगा, जब पानी आयेगा

श्री बागड़ी : कोई ज्योतिष की बात बताइये ।

श्री उमा० प्र० ज्योतिषी : जब हमारे देश में नहरें नहीं बनी थीं, रेलें नहीं बनी थीं, सड़कें नहीं थीं, तब भी मैं कहता हूं कि आप इस देश के इतिहास को पढ़ कर देखें, पुराणों को पढ़ कर देखें, बाढ़ें आया करती थीं और लोगों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ता था, लोगों को गांव के गांव खाली करने पड़ते थे, दूसरी जगहों पर जाकर बसना पड़ता था । इतना निराश होना, इतना मायूस होना जितना हम दिखाई देते हैं, बड़ी ग़लत चीज मुझे लगती है । हम लोगों को उत्तेजित करें यह कह कर कि जो काम किये गये हैं, गलत किये गये हैं, मैं समझता हूं बुरी चीज है । हमारी जिन्दगी जैसी कुछ भी है, उस में हमको हानि और लाभ दोनों चीजों का तखमीना लगाना होगा और देखना होगा कि कोई कदम उठा है तो उसके कितना लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है । जब योजना बनती है, जब सड़कें बनती हैं, जब रेलें बनती हैं, जब यातायात के साधन उपलब्ध होते हैं तो हमें देखना होगा कि उन से कितनी सुविधायें लोगों को प्राप्त होती हैं, कितनी सम्पत्ति देश की बढ़ती है और जब नहरें बनती हैं तो हमें देखना होगा कि उनसे उस प्रदेश में उपज कितनी बढ़ी है, कितना उस प्रदेश को लाभ हुआ है । यह ठीक है कि जब दीपक जलाया जाता है तो उसमें से प्रकाश के साथ धुआं भी निकलता है और उस धुयें को भी हमें बरदाश्त करना पड़ता है । हम योजना करें कि धुआं कम निकले । इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचारकरना होगा । हमें देखना होगा कि जो वाटरलागिंग हो गया है, वह न हो । हम इसके बारे में भी कुछ योजना करें जिससे पानी निकलना शुरू हो सके, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पानी से हम छुटकारा पा सकें । हमें कोशिश करनी होगी कि हमारी फसलें न डूबें, उनको हानि न पहुंचे । लेकिन इसके लिये करोड़ों की सम्पत्ति हम एक दम से डाल दें, ऐसा करते वक्त हमें इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना होगा । (इंटरप्शंज) बाढ़ पीड़ितों के प्रति मैं पूरी हमदर्दी रखता हूं कम से कम उतनी हमदर्दी रखता हूं जितनी कि कछवाय साहब को हो सकती है । एक भी भाई की एक इंच जमीन भी अगर डूबती है, एक बच्चे को भी अगर भूखे रहना पड़ता है, एक भी आदमी को अगर पानी में रहना पड़ता है, तो उसके साथ जितनी कछवाय साहब को हमदर्दी है, उतनी ही मुझको भी है और मुझको शायद उनसे ज्यादा ही हमदर्दी है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर ऐसी बात है तो आप इस भाषा को न बोलते ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : आप शायद मेरी भाषा नहीं समझ रहे । देश के पैसे को जिस किसी काम में हम लगायें हमें देखना होगा कि आया वह पैसा उत्पादक कार्यों में लगाया जा रहा है या अनुत्पादक कार्यों में । यह देख लेना बहुत जरूरी है । बाढ़ों के लिये जो रुपया रखा जाए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जो भी रुपया रखा जाए और बाढ़ें न आ सकें, इस हेतु जो भी रुपया रखा जाए, इस हेतु प्लानिंग करने के लिए जो भी रुपया रखा जाए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन मैं चाहूंगा कि देश की पाई पाई का अधिक से अधिक उत्पादक चीजों के लिए उपयोग हो । अगर पंजाब में या उत्तर प्रदेश में नहरों के कारण बाढ़ें आने लगी हैं तो मैं कहता हूं कि वहां पर आप नहरें बनाना छोड़ कर मध्य प्रदेश में नहरें बनायें । मध्य प्रदेश भूखा है, मध्य प्रदेश प्यासा है, वहां की नदियों पर आप बांध लगाइये । वहां कोई वाटरलागिंग नहीं है । उत्तर प्रदेश की नदियों में पानी है और वह बेतहाशा बहता रहता है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है । वहां पर आप नहरें डालिये, वहां पर तालाब बनाइये, वहां पर सिंचाई का इंतजाम कीजिये, अपने रुपये को उस तरफ डाइवर्ट कीजिये ताकि वह रुपया उत्पादक कार्यों में लग सके ।

यही मुझे निवेदन करना था ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, यदि जवाब कल दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा ।

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): Mr. Speaker, Sir, I must express my very grateful thanks to the hon. Members of the House for the very valuable suggestions that they have given.

Mr. Speaker: Would he like to continue tomorrow?

Dr. K. L. Rao: I can finish in fifteen minutes, Sir. I shall be brief in my reply.

अध्यक्ष महोदय : जब हाउस की यह मर्जी है तो फिर कल ही पर इसे रखिये ।

18.47 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the October 1, 1964/Asvina 9, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS II—1294 (ai) LSD—12-10-64—970.